सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

"जिन्दगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता, कभी वक्त रास्ता चुनता है, तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं...!!"

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–153 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, सोमवार 22 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

अबूझमाड़ के जंगलों पर खतरा, रोज 70 हेक्टेयर तक वन कटाई का आरोप, नितिन सिंघवी ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र,

भूमि सर्वेक्षण तक निर्माण कार्यों पर रोक की मांग

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

31 मार्च 2026 को बस्तर को वामपंथी उग्रवाद मुक्त घोषित किए जाने के बाद से अबूझमाड़ क्षेत्र के नारायणपुर जिले में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की सूचनाएं सामने आ रही हैं। रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन गतिविधियों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

रोज 50 से 70 हेक्टेयर जंगल साफ होने का दावा

सिंघवी ने पत्र में लिखा है कि सड़क निर्माण, वन भूमि को कृषि भूमि में बदलने, झूम खेती और इमारती लकड़ी की तस्करी के नाम पर आधुनिक जेसीबी, डोजर और भारी मशीनों से प्राकृतिक वनों को तेजी से साफ किया जा रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 50 से 70 हेक्टेयर वन क्षेत्र विभिन्न कारणों से नष्ट किया जा रहा है।

भारत के फेफड़े कहलाता है अबूझमाड़

लगभग 5000 से 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला अबूझमाड़ मध्य भारत के सबसे बड़े सतत वन क्षेत्रों में से एक है। यह विशाल वन क्षेत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर जलवायु संतुलन बनाए रखता है। इसी कारण इसे भारत के फेफड़ों के समान अमूल्य प्राकृतिक धरोहर माना जाता है। यह जंगली भैंसा, बाघ, तेंदुआ, भालू समेत अनेक दुर्लभ वन्यजीवों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास भी है।

भूमि सर्वेक्षण नहीं, फिर भी हो रही कटाई

सिंघवी ने कहा कि अबूझमाड़ का आज तक विधिवत भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ है। यहां यह अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं कि कौन सी भूमि राजस्व विभाग की है और कौन सी वन विभाग की। वतर्मान में भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है। सवीच्च न्यायालय के टीएन गोदावर्मन प्रकरण के अनुसार प्राकृतिक वन क्षेत्र प्रथम दृष्टया डीम्ड फॉरेस्ट की श्रेणी में आते हैं। इसके बावजूद अनेक स्थानों पर भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से पहले ही सड़क निर्माण और अन्य अधोसंरचना कार्यों के लिए बड़ी संख्या में परिपक्ववृक्षों की कटाई की जा रही है।

वन अधिकार अधिनियम को लेकर फैली अफवाह

सिंघवी ने बताया कि स्थानीय लोगों के बीच अफवाह फैलाई जा रही है कि 31 मार्च 2026 से एक वर्ष के भीतर जंगल काटकर कब्जा कर खेती शुरू कर दी जाए तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत उस भूमि का पट्टा मिल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 13 दिसंबर 2005 या उससे पूर्व का कब्जा तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए उससे पूर्व लगातार तीन पीढ़ियों का निवास और वन पर निर्भरता सिद्ध करना अनिवार्य है। आधुनिक सैटेलाइट तकनीक से यह आसानी से सत्यापित किया जा सकता है कि भूमि पर वास्तविक कब्जा कब से है।

अधिकारियों ने मानी स्टाफ की कमी

पत्र में उल्लेख है कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने स्वीकार किया है कि यदि एक मामले में कारर्वाई की जाए तो सैकड़ों मामलों में कारर्वाई करनी पड़ेगी, जिससे व्यापक असंतोष हो सकता है। वन विभाग के एक अधिकारी ने भी माना कि इन क्षेत्रों में रेंजर, डिप्टी रेंजर और वनरक्षक तक पदस्थ नहीं हैं, जिसका कुछ लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

अबूझमाड़ बचाने के लिए तीन सुझाव

सिंघवी ने मांग की है कि अबूझमाड़ के अनसर्वेक्षित क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण पूर्ण होने तक वृक्षों की कटाई वाले सड़क और अन्य अधोसंरचना कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। वन अधिकार अधिनियम को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्थानीय भाषाओं में जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही वन कटाई, अवैध लकड़ी तस्करी और नए अतिक्रमणों को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की सहायता ली जाए।

सिंघवी ने कहा कि अबूझमाड़ केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि पूरे भारत की प्राकृतिक धरोहर है। यदि आज इस वन संपदा को बचाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि जनता यह सोचे कि जब अबूझमाड़ अशांत था तब जंगल सुरक्षित थे और अब शांति के समय जंगल तेजी से समाप्त हो रहे हैं।

स्कूली बसों की सुरक्षा जांच: 51 में से 5 बसों पर कार्रवाई, 13 चालकों में मिली स्वास्थ्य समस्या

यातायात पुलिस और परिवहन विभाग का संयुक्त शिविर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हुई जांच

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-भिलाई

स्कूली छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को लेकर यातायात पुलिस दुर्ग और परिवहन विभाग ने शनिवार को पुलिस ग्राउंड सेक्टर-6 भिलाई में संयुक्त स्कूल बस जांच शिविर लगाया। शिविर में जिले के 4 शैक्षणिक संस्थानों की 51 स्कूल बसों का विस्तृत निरीक्षण किया गया।

सुरक्षा मानकों में खामी पर 5 बसों का चालान

जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों और जरूरी दस्तावेजों में खामी पाए जाने पर 5 स्कूल बसों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। संबंधित संचालकों को कमियों का निराकरण करने के बाद ही बसों का संचालन करने के निर्देश दिए गए।

जीपीएस से लेकर फायर किट तक की हुई जांच

परिवहन विभाग ने वाहन पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, रोड टैक्स और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस का परीक्षण किया। बसों की मैकेनिकल फिटनेस के तहत हेडलाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, टायर, स्टीयरिंग, क्लच, एक्सीलेटर, हॉर्न, वाइपर, सीट व्यवस्था और रिफ्लेक्टर आदि की जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट के मानकों के अनुसार स्कूल बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन निकास, प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निशमन यंत्र, स्कूल का नाम, संपर्क नंबर तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया गया।

13 चालकों में मिली बीपी और शुगर की शिकायत

शिविर के दौरान चालक और परिचालकों के स्वास्थ्य परीक्षण भी कराए गए। इसमें 13 चालकों में रक्तचाप और शुगर संबंधी स्वास्थ्य शिकायतें पाई गईं। इन चालकों को आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिया गया। बस संचालकों को सभी सुरक्षा मानकों की पूर्ति के बाद ही वाहनों का संचालन करने और अनुपस्थित बसों की आगामी शिविर में अनिवार्य जांच कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

बीएसपी में 'चोरों का दफ्तर', 3.85 करोड़ का स्क्रैप घोटाला सीआईएसएफ की नाक के नीचे चल रहा था काला साम्राज्य

250 टन माल जब्त, 12 गिरफ्तार, बीएसपी और सीआईएसएफ अफसरों के नाम उजागर, कुछ जनप्रतिनिधि भी रडार पर

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

देश के सबसे सुरक्षित औद्योगिक संयंत्रों में गिने जाने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बीएसपी के भीतर ही लौह स्क्रैप चोरी का संगठित रैकेट चल रहा था। आरोपियों ने प्लांट परिसर में ही अपना 'अनौपचारिक दफ्तर' बना रखा था जहां से चोरी का पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता था। पुलिस ने मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटा लिए हैं।

26मई को हुआ था 3.85 करोड़ का भंडाफोड़

भिलाई-3 थाना पुलिस ने 26 मई को ग्राम अकलोरडीह स्थित एके ट्रेडर्स में छापा मारकर बीएसपी के फ्लू डस्ट और कीमती लौह स्क्रैप की बड़ी खेप बरामद की थी। गोदाम, हाइवा और ट्रकों में लोड करीब 250 टन स्क्रैप जब्त हुआ। बोरियों में भरा माल, वाहन और मशीनरी मिलाकर कुल 3.85 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई।

सीसीटीवी से खुली प्लांट तक की कड़ी

एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देशन में विशेष टीम ने अकलोरडीह से बीएसपी प्लांट तक की कड़ी जोड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच दल ने फ्लू डस्ट लोडिंग प्वाइंट और एसएमएस-3 स्क्रैप यार्ड का निरीक्षण किया। यहीं से बड़ी मात्रा में स्क्रैप चोरी होने की आशंका है। पुलिस को प्लांट परिसर के भीतर उस स्थान की जानकारी मिली जहां से चोरी का नेटवर्क संचालित हो रहा था।

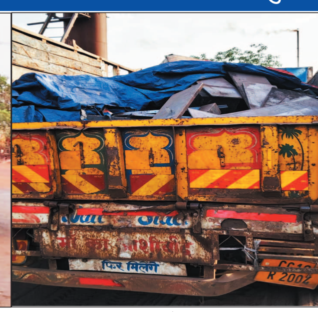

'महोदय जी' के करीबी पर संदेह, कुछ जनप्रतिनिधि रडार पर

पुलिस सूत्रों के मुताबिक बड़े पैमाने पर स्क्रैप चोरी राजनीतिक संरक्षण में हो रही थी। जिस दिन भंडाफोड़ हुआ, उसी दिन संजय सिंह ने 'महोदय जी' के करीबी को फोन किया था। उसे आश्वासन मिला था कि "कुछ नहीं होगा"। 'महोदय जी' के करीबी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इसके अलावा शहर के कुछ जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है।

हिस्ट्रीशीटरों की प्लांट में एंट्री, वसूली का खेल

जांच में सामने आया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों की प्लांट के अंदर एंट्री हुई है। इसमें दो हिस्ट्रीशीटर के अलावा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति द्वारा प्रोटेक्शन मनी वसूलने की बात भी सामने आई है। ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े कुछ लोग, कथित वसूली नेटवर्क और चोरी का माल खरीदने वाली औद्योगिक इकाइयों की भी जांच चल रही है।

क्या बोले अफसर

सीएसपी भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि बीएसपी से चोरी और आपराधिक कृत्यों से बनाई गई संपत्ति की भी छानबीन की जा रही है और रिकवरी कराई जाएगी। आरोपियों के कथन के आधार पर आगे विवेचना की जा रही है। इस संगठित अपराध में संदेहियों से पूछताछ की जाएगी। एएसपी शहर सुखनंदन राठौर ने कहा कि क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया गया है। संगठित नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच जारी है।

इस खुलासे के बाद बीएसपी प्रबंधन, सीआईएसएफ और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के संवेदनशील औद्योगिक संयंत्र के भीतर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चलता रहा और सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी।

सोने के जेवर, डेढ़ करोड़ का प्लॉट: काली कमाई का निवेश

पूछताछ में सामने आया कि चोरी की कमाई को सोने के आभूषणों और संपत्तियों में लगाया गया। पुलिस ने संजय सिंह के बैंक लॉकर से लाखों रुपए के सोने के आभूषण जब्त किए हैं। इनका बाजार मूल्यांकन कराया जा रहा है। सुपेला स्थित प्रियदर्शिनी परिसर में करीब डेढ़ करोड़ रुपए मूल्य के एक प्लॉट के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया मास्टरमाइंड

मामले के मुख्य किरदार इनामी ट्रांसपोर्टर संजय सिंह को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। सात दिन की रिमांड में पूछताछ के दौरान संजय ने चोरी का तरीका बताया और बीएसपी व सीआईएसएफ के अधिकारियों-जवानों के नाम उजागर किए। संजय की निशानदेही पर आकाश सिंह को गिरफ्तार किया गया जो चोरी का स्क्रैप राजनीतिक संरक्षण में खपाता था। अब तक संजय सिंह समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने वाहन, मशीनरी और अन्य संपत्तियों सहित करीब 3 .22 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।

बीएसपी-सीआईएसएफ अफसरों से पूछताछ की तैयारी

गिरफ्तार संजय सिंह और आकाश सिंह ने पूछताछ में बीएसपी के कुछ अधिकारियों और सीआईएसएफ के अधिकारियों-जवानों के नाम उजागर किए हैं। पुलिस अब इन संदेही अधिकारियों और जवानों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। संजय सिंह, आकाश सिंह और अंकित शर्मा की पुलिस रिमांड 22 जून को पूरी हो रही है। पुलिस तीनों को कोर्ट में पेश करेगी। जरूरत पड़ी तो फिर से रिमांड मांगी जा सकती है।

राजनांदगांव में पुलिस की सरप्राइज चेकिंग, 150 जवानों ने खंगाले रिसॉर्ट

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

मनगटा में पुलिस ने रविवार को बड़े पैमाने पर सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगभग 150 पुलिस बल और राजपत्रित अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र के रिसॉर्टों की जांच की।

25-25 की टुकड़ी बनाकर की गई कार्रवाई

पुलिस ने 25-25 जवानों की टुकड़ी बनाकर सभी चालू और बंद रिसॉर्टों की सघन जांच की। बंद पड़े रिसॉर्टों को भी चेक किया गया। पुलिस अवैधानिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

भिलाई की युवती की संदिग्ध मौत के बाद अवैधानिक गतिविधियों पर सख्ती

युवती की मौत के बाद बढ़ी सख्ती

भिलाई की एक युवती की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इस तरह की औचक जांच आगे भी जारी रहेगी।

खास खबर

कुरूद में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह, पांच बुजुर्ग "जीवन गौरव सम्मान" से सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

घनश्याम देवांगन बोले : वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर, नई पीढ़ी इनके अनुभव से सीखे

वरिष्ठ नागरिक पर्यटन मंच के तत्वावधान में बालाजी होटल कुरूद में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पांच वरिष्ठ नागरिकों को "जीवन गौरव सम्मान" से सम्मानित किया गया। भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के अध्यक्ष घनश्याम कुमार देवांगन समारोह के

मुख्य अतिथि रहे।

वरिष्ठ नागरिकों ने रखी समाज की नींव: देवांगन : समारोह को संबोधित करते हुए महासंघ अध्यक्ष घनश्याम देवांगन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का जीवन अनुभव, संघर्ष, समर्पण और सफल पारिवारिक जीवन का आईना होता है। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने परिश्रम, त्याग और संस्कारों से परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम जिस सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक मूल्यों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उसकी मजबूत नींव इन्हीं के प्रयासों से रखी गई है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी अपने वरिष्ठजनों के अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकती है।

इन्हें मिला जीवन गौरव सम्मान : जीवन गौरव सम्मान से सम्मानित होने वालों में छालीवुड कलाकार लाल बहादुर चंद्रा, हुकुमचंद देवांगन, श्रीमती निरुपा सहारे, श्रीमती बेदू साहू और मुकुंद दास साहू शामिल हैं। सभी को अभिनंदन पत्र, शॉल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।

मथुरा वृंदावन भ्रमण की योजना : इस अवसर पर किशनलाल सोनी, ताम्रध्वज सहारे, श्रीमती छाया चंद्रा, श्रीमती सावित्री देवांगन, श्रीमती सुनीता सोनी विशेष रूप से उपस्थित थे। संयोजक हुकुमचंद ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का सामूहिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आगामी दिनों में मथुरा वृंदावन भ्रमण की योजना बनाई गई है।

बीएसपी की सुरक्षा, विस्तार और रोजगार पर विधायक सेन ने की चर्चा

कार्यपालक निदेशक पवन कुमार से सौजन्य भेंट, लौह चोरी रोकने और औद्योगिक विकास पर हुई बातचीत

भिलाई। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने शनिवार को भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के कायर्पालक निदेशक पवन कुमार से सौजन्य भेंट कर संयंत्र की सुरक्षा, उत्पादन, विस्तार और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

लौह चोरी पर चिंता : विधायक सेन ने संयंत्र में वर्षों से सामने आती रही लौह एवं स्क्रैप चोरी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा सवीच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना आवश्यक है।

प्लांट विस्तार और रोजगार पर जोर : बैठक में बीएसपी के विस्तार, आधुनिकीकरण और नई परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। विधायक सेन ने कौशल विकास और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की बात रखी।

श्रमिक हित भी रहे केंद्र में : श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, कार्यस्थल की बेहतरी और कमर्चारी हितों से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। विधायक सेन ने श्रमिक कल्याण को औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया।

समन्वय से होगा विकास : दोनों पक्षों ने भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रगति, सुरक्षा और क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए निरंतर संवाद एवं सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। विधायक सेन ने विश्वास व्यक्त किया कि बीएसपी के सशक्त होने से क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

शासकीय भूमियों के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन सख्त

दुर्ग। जिला प्रशासन द्वारा शासकीय संपत्तियों एवं भूमियों के संरक्षण तथा अवैध कब्जों व अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए मैदानी स्तर पर निरंतर सजगता से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में अनुभाग धमधा के अंतर्गत ग्राम धरमपुरा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में राजस्व विभाग द्वारा त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है।

भिलाई में 'वेस्ट से बेस्ट' की मिसाल, महिला समूह कबाड़ से बना रही सजावटी सामान

एसएलआरएम सेंटर खुर्सीपार में तैयार हो रहे गमले, शोपीस और गार्डन डेकोरेशन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 42 गौतम नगर खुर्सीपार स्थित एसएलआरएम सेंटर में मणीकंचन महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वच्छता और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। यहां वार्डों से प्रतिदिन एकत्र होने वाले कचरे और कबाड़ सामग्री को उपयोगी एवं आकर्षक सजावटी वस्तुओं में बदलकर 'वेस्ट से बेस्ट' की अवधारणा को साकार किया जा रहा है।

कबाड़ से तैयार हो रहे गमले और शोपीस

एसएलआरएम सेंटर में पहुंचने वाले सूखे कचरे का पृथक्करण कर प्लास्टिक, टायर, बोतल, डिब्बे और अन्य अनुपयोगी सामग्रियों को अलग किया जाता है। इसके बाद महिला समूह की सदस्य इन कबाड़ वस्तुओं से सुंदर गमले, सजावटी शोपीस, गार्डन डेकोरेशन सामग्री, हैंगिंग आइटम, टेबल डेकोरेशन और घरों के प्रवेश द्वार को आकर्षक बनाने वाले उत्पाद तैयार कर रही हैं।

पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार भी

महिलाओं द्वारा तैयार सामग्री पर्यावरण संरक्षण में सहायक है और लोगों को कचरे के पुनः उपयोग के प्रति जागरूक कर रही है। इन उत्पादों का उपयोग घरों, कार्यालयों और उद्यानों की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने कहा कि इस पहल से कचरे का बेहतर प्रबंधन हो रहा है और महिला समूहों को रोजगार एवं आय का अतिरिक्त स्रोत भी मिल रहा है।

नागरिकों ने की सराहना

महिला समूह की इस पहल की स्थानीय नागरिकों ने सराहना की है। लोगों का मानना है कि ऐसे प्रयास शहर को स्वच्छ बनाने में मदद करते हैं और समाज में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। यह प्रयास स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

जेके लक्ष्मी सीमेंट दुर्ग में रक्तदान शिविर आयोजित, 489 लोगों ने किया रक्तदान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

जेके लक्ष्मी सीमेंट दुर्ग में पद्म भूषण स्व. हरिशंकर सिंघानिया की 93वीं जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 489 लोगों ने रक्तदान किया। आयोजन का उद्देश्य समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाना था। कार्यक्रम की शुरुआत हरिशंकर सिंघानिया के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। शिविर संयंत्र प्रमुख राजपाल सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इसमें प्लांट में कार्यरत कमर्चारी, विभिन्न ठेका कंपनियों के श्रमिक और आसपास के ग्रामीणों ने सहभागिता की।

इस अवसर पर प्लांट प्रमुख राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि हरिशंकर सिंघानिया एक सफल उद्यमी के साथ समाजसेवी भी थे। उन्होंने हमेशा समाज में सेवा भाव से काम किया जिसके कारण उन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। उनके जन्म दिवस पर पूरे भारत में जेके ऑगर्नाइजेशन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि जरूरतमंद लोगों तक रक्त पहुंच सके। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख मनीष तिवारी ने बताया कि दुर्ग जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट में पिछले 11 वर्षों में लगभग 6000 यूनिट रक्तदान किया गया है। इस पुनीत कार्य के लिए पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने दुर्ग प्लांट को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया।

शिविर में अहिवारा नगर पालिका अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा और अन्य पार्षद भी उपस्थित हुए और रक्तदान में भाग लिया। रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी रायपुर, बिलासा ब्लड बैंक, बालाजी ब्लड बैंक और दुर्ग जेके लक्ष्मी सीमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर की संयुक्त प्रशिक्षित टीम ने किया। इस दौरान संयंत्र प्रमुख राजपाल शेखावत, मानव संसाधन प्रमुख मनीष तिवारी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर के डॉ. अमित यादव, विभाग प्रमुख, कर्मचारी और श्रमिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

कुटेश्वर माइंस में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण, नई डेंटल चेयर का उद्घाटन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर ने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशिक किशोर के साथ कुटेश्वर माइंस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुटेश्वर चिकित्सालय और डिस्पेंसरी में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का अवलोकन किया।

दौरे के समय डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर ने कुटेश्वर डिस्पेंसरी में नई डेंटल चेयर का उद्घाटन किया। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, रोगी सुविधाओं और स्वास्थ्य अधोसंरचना का निरीक्षण किया। चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। साथ ही गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी चुनौतियों, जरूरतों और सुधार की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ. ठाकुर ने रोगी देखभाल की गुणवत्ता में निरंतर सुधार और चिकित्सा सुविधाओं के प्रभावी संचालन के लिए सुझाव दिए। उनके मार्गदर्शन से कुटेश्वर माइंस में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

कुटेश्वर माइंस चिकित्सा टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. विनीता द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार और कुटेश्वर माइंस के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार के सतत मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया।

पाटन ब्लॉक की सहकारी समितियों में खाद व बीज का पर्याप्त भण्डारण, पीएम आवास के 15 अपात्रों पर हुई पारदर्शी कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा खरीफ सीजन 2026 के दौरान कृषकों को सुचारू रूप से कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में पूर्ण पारदशिर्ता बनाए रखने हेतु निरंतर मैदानी स्तर पर समीक्षा एवं जांच की जा रही है। इसी कड़ी में पाटन विकासखंड के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा पर्याप्त खाद-बीज का सुव्यवस्थित भंडारण सुनिश्चित किया गया है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं पारदर्शी कार्रवाई की गई है। कृषि एवं बीज निगम के अधिकारियों ने बताया कि आईएमएफएस पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक विकासखंड पाटन में इस वर्ष खरीफ 2026 में अब तक यूरिया 5556.78 मीट्रिक टन, एसएसपी 2763.07 मीट्रिक टन, पोटाश 1314.60 मीट्रिक टन, डीएपी 1105.05 मीट्रिक टन एवं एनपीके 1026.90 मीट्रिक टन का अद्यतन भंडारण सहकारी समितियों में किया जा चुका है। गत वर्ष खरीफ 2025 की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष यूरिया में 959 मीट्रिक टन, एसएसपी में 460 मीट्रिक टन तथा पोटाश में 506 मीट्रिक टन का अधिक भंडारण दर्ज किया गया है। डीएपी की आंशिक कमी की स्थिति में किसानों को वैकल्पिक एवं अधिक पोषक तत्वों वाले उर्वरकों जैसे एसएसपी , टीएसपी, एनपीके और नैनो डीएपी के उपयोग हेतु लगातार प्रोत्साहित एवं वितरित किया जा रहा है।

बीएसपी में सुरक्षा और डिजिटलीकरण की नई पहलें, कार्यस्थल हादसों पर लगेगी लगाम

मानव-मशीन संपर्क कम करने पर जोर, लैडल ट्रैकिंग सिस्टम और रिमोट क्रेन लागू

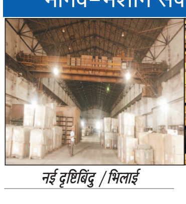

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल भिलाई इस्पात संयंत्र ने कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करने और परिचालन में डिजिटलीकरण बढ़ाने के लिए कई नई तकनीक आधारित पहलें शुरू की हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मानव और मशीन के बीच सीधे संपर्क को कम करना, दुर्घटनाओं की संभावना घटाना और परिचालन दक्षता बढ़ाना है।

ओएचपी में उन्नत जाम पहचान प्रणाली

ओर हैंडलिंग प्लांट में मौजूदा जाम पहचान प्रणाली को उन्नत किया गया है। यहां प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग तकनीक से युक्त इलेक्ट्रो मैकेनिकल टिल्टिंग डिवाइस लगाया गया है। यह प्रणाली कन्वेयर में अवरोध की सटीक पहचान करती है। इससे अनावश्यक ट्रिपिंग रुकेगी और सामग्री के ओवरफ्लो की आशंका कम होगी। उपकरणों की विश्वसनीयता और परिचालन सुरक्षा भी बढ़ेगी।

बीआरएम में सुरक्षित क्रेन बोर्डिंग प्रणाली

बार एवं रॉड मिल में क्रेन परिचालन के दौरान कमियों की सुरक्षा के लिए नई क्रेन बोर्डिंग प्रणाली विकसित की गई है। इसके जरिए ऑपरेटर की मदद से क्रेन को सुरक्षित रूप से रोका जा सकता है। इससे अचानक रुकने, लोड के अनियंत्रित झूलने और अन्य जोखिम कम होंगे। क्रेन पर टॉगल स्विच सक्रिय होने पर ऑपरेटर के केबिन में संकेतक प्रकाश जलता है। इससे सुरक्षित रूप से क्रेन रोककर कमियों के चढ़ने और संचालन शुरू करने की प्रक्रिया पूरी होती है।

एसएमएस-2 में रिमोट नियंत्रित क्रेन

स्टील मेल्टिंग शॉप-2 के बोरिया स्टोर कॉम्प्लेक्स में रेडियो रिमोट नियंत्रित ओवरहेड क्रेन प्रणाली लागू की गई है। अब ऑपरेटर बेहतर दृश्यता वाले सुरक्षित स्थान से क्रेन चला सकेंगे। इससे लटके हुए भार के संपर्क में आने का खतरा कम हुआ है। आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और सामग्री प्रबंधन की दक्षता भी बढ़ी है।

एसएमएस-3 में एआई आधारित लैडल ट्रैकिंग

स्टील मेल्टिंग शॉप-3 में उन्नत लैडल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। यह प्रणाली स्वचालन, रियल टाइम मॉनिटरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण से लैस है। इससे लैडल की स्थिति और गतिविधियों की सतत निगरानी संभव हुई है। निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनी है और मैनुअल हस्तक्षेप कम हुआ है।

सुरक्षा मानकों को मिलेगा बढ़ावा

मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री देबदत्त सतपथी ने बताया कि ये पहलें संयंत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने और कमर्चारी केंद्रित कार्य संस्कृति विकसित करने के अभियान का हिस्सा हैं। तकनीक आधारित सुरक्षा उपायों से बीएसपी सुरक्षित, दक्ष और आधुनिक कार्यस्थल के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सोलह दूनी आठ
नई दृष्टिबिंदु

अब कैसे करेंगे

साप्ताहिक कॉलम

याज्ञवल्क्य मिश्रा

पहले बस्तर को लेकर यह था कि, छुटभैया से लेकर बल्लम नेताजी लोग किसी सरकारी नुमाइंदे से नाराज होते थे तो धमकाते थे कि, बस्तर भेज देंगे। कई बार भेज भी देते थे। अब मसला ये है कि कहां भेजेंगे। एक मसला ये भी है कि पहले नक्सली का डर दिखा कर सारे छोटे बड़े कांड होते थे और ढाँप दिए जाते थे। सरहदी इलाके की रेत हो या लकड़ी या फिर जंगल के शेड्यूल वन के जानवरों के शव सब धड़ल्ले से सरहद पार होते थे। सड़क पुल बाँध कागज में बनते थे कागज में क्षतिग्रस्त होकर रिपेयर होते थे और फिर किसी साल तेज बारिश में बहकर फिर से बनाया जाए के प्रस्ताव में बदलते थे, और भी जाने कितने काले पीले। अब इस तरह की जुगत करने वालों के साथ मसला बस ये है कि, कुछ तो रुक जाएगा और रेत लकड़ी समेत होने वाले खुल्लाखेल फर्रुखाबादी में सहकारिता का प्रवेश होगा और सभी सुशासन सरकार की जय करेंगे। याने ये कि विकास और तेजी से होगा। अब चाहे जिस तरह से हो और जिसका हो।

ये अफवाह कौन उड़ाया

भली भली सी सरकार है। प्यारा सा नाम है सुशासन सरकार। लोग आंय बांय बोलते रहते हैं,सवाल उठाते रहते हैं। जबकि सहाफी इसी कॉलम में कई बार लिख पढ़ चुका है कि इस सरकार में जिस सरकारी काम का अर्थ प्रसंग समझ ना आए उसे ही सुशासन कहा जाता है। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। अब देखिए कोई पूरी ताक़त से पतंग उड़ा रहा है कि ये जो नए नवेले आईपीएस वंश के लोग हैं इनका जंगल वार फेयर ट्रेनिंग नहीं हुआ है,और ऐसा एक नहीं बल्कि हालिया के तीन तीन बैच के साथ हो गया है। अब इसमें लेकिन हल्ला काहे हो रहा है। जब हो रहा था तो सरकार का फैसला था। अब नहीं हो रहा है तो भी सरकार का फैसला है। चलिए हो सकता है सुशासन सरकार भूल गई हो गई तो इतना सारा काम (?) सरकार को करना पड़ता है, कुछ भूल भी गई तो क्या ही हो गया, और अब काहे का जंगल वार फेयर ट्रेनिंग। सरकार काल याने समय को जीतने का ज्ञान जानती है। उसे पता है अब माओवाद खत्म हो गया कभी नहीं लौटेगा। मच्छर वाला दृष्टान्त और हर बीस बरस में माओवाद के करीब करीब शून्य पर जाने और फिर वापस और ताक़त से उठ खड़े होने की बातें केवल बातें हैं।

क्या गजब करते हो जी

पुलिस वो भी सुशासन सरकार की। अगर गजब ना करे तो फिर काहे की पुलिस। देखिए हुआ ये कि, जादूगर मैंड्र्क के कॉमिक्स कथा की तरह एमसीबी पुलिस ने कोरिया के लल्ला सिंह हत्याकांड में पांच आरोपियों को लेकर बताया कि, इन्होंने हमारे यहां सरेंडर कर दिया है ।प्रेस ने सवाल किया कि ये लोग थे कहां तो जवाब आया मामला कोरिया पुलिस का है कोरिया पुलिस बताएगी। अब आगे ये हुआ कि आरोपियों को कोरिया पुलिस के हवाले कर दिया गया। यहां और मस्त हुआ। लल्ला सिंह को ज़िंदा जलाया गया सोनहत थाने के नौगई में। आरोपी नौगई गांव के ही हैं। लेकिन कोरिया पुलिस ने देर रात उनका जुलूस निकाला पटना थाना में। अब सोनहत और पटना के बीच की दूरी है करीब करीब 65 किलोमीटर। पटना में जुलूस निकाल पुलिस ने माना कि उसने सोनहत इलाके से आरोपियों का डर खत्म कर दिया है। इन शॉर्ट फिर से समझिए। मामला कोरिया जिले के सोनहत थाने का,सरेंडर किया एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ थाने में और कोरिया पुलिस ने जुलूस निकाल दिया पटना थाना में। अब ये उपक्रम आपको विचित्र लगे तो लगता रहे। अपने राम तो सुशासन सरकार के साथ और बिलाशक पुलिस के साथ। अगर पुलिस को लगता है कि,किसी अपराधी का दबदबा रायपुर में है लेकिन बिलासपुर में जहां अपराधी को कोई नहीं जानता,वहां जुलूस निकालने से रायपुर में छाया डर खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा।

जीरो टॉलरेंस तो ठीक है सर लेकिन

सुशासन सर अक्सर बोलते हैं करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। अब सुशासन सर बोलते हैं मतलब तंत्र मशीनरी उसी अंदाज में काम करती ही होगी। लेकिन फिर रेत मामले में सुशासन का लोटा क्यों गिर रहा है। मसला ये है जीरो टॉलरेंस हो तो हो कैसे। एक दिलजले ने सहाफी से कहा – देखो पत्रकार जी,तीन मंत्री और करीब सत्रह विधायक खुद ही धकापेल रेत के वैध अवैध दोनों क़ि स्म के कारोबार में शामिल हैं ।अब सुशासन सरकार के जीरो टॉलरेंस का लोटा नहीं गिरेगा तो और क्या होगा।

खत का अपना किस्सा

छत्तीसगढ़ में खासकर पुलिस महकमे में चिट्ठी का अपना प्रताप है। वो भी खासकर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के संदर्भ में। ये अलग बात है कि, होता जाता ठेंगे से कुछ भी नहीं ।इस सरकार के कार्यकाल में पहली चिट्ठी वायरल हुई गरियाबंद के डीएसपी की ।इस महिला डीएसपी ने पत्र में लिखा कि,पद से ज्यादा पोस्टिंग हो रही है। नतीजा ये है कि ना मकान मिल रहा है और ना ही वर्क स्पेस। दूसरी चिट्ठी वायरल हुई एक एसपी की। इन साहब का दर्द ए डिस्को ये था कि इन्हें आईपीएस प्रमोशन नहीं मिला। साहब ने बाक़ी अफसरों के केस मुकदमे लिखे और बोले कि जब इन लोगों का प्रमोशन हो सकता है तो मैंने किस की भैंस पर डंडा चला दिया था। तीसरी चिट्ठी लिखी एक एडिशनल एसपी साहब ने। इस भाई का कहना है कि एक खाली और निरुपयोगी कमरे में सामान रखे थे।

वो बात

मुख्यमंत्री निवास में हुई समीक्षा बैठक में जिस विषय की सबसे ज्यादा चर्चा थी वह था लॉ एंड ऑर्डर। संगठन ने सवाल किया कि,कोरिया में क्या हुआ और जो हुआ उसके बाद हमने ऐसा क्या किया कि यह लगे कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। हिंदू ह्रदय सम्राट ने जो भी जवाब दिया उन्हें दो टूक कहा गया– ह्लसामने कोई हो और इनके पीछे कोई हो। किसी को नहीं बख़्शा जाए। पूरी दृढ़ता से कार्यवाही होनी चाहिए ।ह्व यही बात सीएम साय ने भी कही लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ ? इसी कॉलम में छपी दो रिपोर्ट को पढ़ लीजिए।

खत का अपना किस्सा

छत्तीसगढ़ में खासकर पुलिस महकमे में चिट्ठी का अपना प्रताप है। वो भी खासकर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के संदर्भ में। ये अलग बात है कि, होता जाता ठेंगे से कुछ भी नहीं ।इस सरकार के कार्यकाल में पहली चिट्ठी वायरल हुई गरियाबंद के डीएसपी की ।इस महिला डीएसपी ने पत्र में लिखा कि,पद से ज्यादा पोस्टिंग हो रही है। नतीजा ये है कि ना मकान मिल रहा है और ना ही वर्क स्पेस। दूसरी चिट्ठी वायरल हुई एक एसपी की। इन साहब का दर्द ए डिस्को ये था कि इन्हें आईपीएस प्रमोशन नहीं मिला। साहब ने बाक़ी अफसरों के केस मुकदमे लिखे और बोले कि जब इन लोगों का प्रमोशन हो सकता है तो मैंने किस की भैंस पर डंडा चला दिया था। तीसरी चिट्ठी लिखी एक एडिशनल एसपी साहब ने। इस भाई का जख़्म इसके पुराने ज़िले से जुड़ा है ।पुराने ज़िले वालों ने बत्तमीजी की पराकाष्ठा करते हुए ताला तोड़ सामान ट्रक में डाल रवाना कर दिया। भाई गांधीगिरी पर उतर गया है। जिस ट्रक में सामान भेजा गया है वह ट्रक सामान सहित लाइन में खड़ा है क्योंकि एडिशनल एसपी भाई ने पुराने ज़िले के आरआई को बोला है पंचनामा कर के दो। अब जहाँ तक चिट्ठी का मसला है तो जो बाक़ी जो चिट्ठियों का हश्र हुआ वही हाल यहाँ भी हुआ है।

फिर दिल ले गई सरकार

भली भोली और सीधी यह है अपनी सुशासन सरकार। क़हर ये है कि सरकार शमिर्ली भी है। नवाचार करती है तो बताती भी नहीं है,खुद ही सोचना समझना पड़ता है कि ये हुआ तो इसके पीछे सरकार का सुशासन नवाचार क्या है,और उसके बाद सरकार एक फिर सहाफी का दिल लूट ले जाती है। जैसे देखिए एक मसला समझाते हैं। क्या है कि एक जिले में जो जातीय समीकरण समुच्चय के हिसाब से संवेदनशील है,बॉर्डर से लगा सटा है,वहां एक महीने से एसपी ही नहीं है। पुराने वाले प्रतिनियुक्ति पर चल दिए हैं। एडिशनल एसपी के भरोसे जिला चल रहा है। वैसे ही जैसे बीच में कोंडागांव और जीपीएम का हाल था। तो कोंडागांव और जीपीएम में तो खैर हाल थोड़े दिन का था लेकिन इस जिले में विदाउट ब्रेक मामला जारी है। अब सरकार के आलोचकों को देखिए,इसी बात पर सरकार की दुर्गति कर रहे हैं कि बताईए कैसी सरकार है जिले में एक एसपी पोस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन अपने राम हैं सरकार के मुरीद। अपने को आदत है हर सरकारी काम को पॉजीटिव देखने की। तो अपने को यह पता चला है कि,सरकार दरअसल पुलिस महकमे के बगैर जिला चल सकता है या नहीं चल सकता इस परीक्षण पर जुटी है,चुंकि सरकार शर्मीली है इसलिए यह बात किसी को बता नहीं रही है और चुपचाप कर रही है। सुशासन सरकार ऐसा करते हुए नागरिकों को कर्तव्य बोध से भरना भी चाहती है कि,ऐसे अनुशासन में रहें कि पुलिस महकमे की जरुरत ही ना पड़े। अब कहीं पर एसपी गोल,कहीं पर डीएसपी नदारद,कहीं टीआई नहीं तो कहीं सिपाहियों की नफरी कम। ये सब दरअसल उसी प्रयोग का हिस्सा हैं। लेकिन ये सरकार के विरोधी लोग शमिर्ली सरकार के नवाचार को समझे बगैर कुछ भी हल्ला मचाने लगते हैं।

कॉपी कैट जर्नलिज्म

सीएम हाउस में मंत्रियों और संगठन की बैठक हुई। यह बैठक हुई कि,ढाई बरस बीत गए हैं अब काउंट डाउन शुरु है। लेकिन कॉपी कैट जर्नलिज्म में खबरें तैर गई कि मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है ।सभी के इस्तीफे लिए जाएंगे। बौद्धिक संपदा पर स्वंयभू कॉपीराइट धारी इन स्वनाम धन्य पत्रकारों की भीड़ इतनी व्यस्त और हड़बड़ी में थी, एक ही खबर का कॉपी पेस्ट होता रहा। कहीं पैराग्राफ बदल गया हो तो बात अलग है। रात को बारह बजे के बाद तक कैमरे के साथ टोली तैनात रही। ऐसी व्यग्रता और उत्कंठा कि, कुछ ने तो ये चार के इस्तीफे हुए और ये नए चार अब बन रहे मंत्री की खबर भी चेंप दी। चलिए जो हुआ सो हुआ ।अब पाठक और दर्शक कितनी सहजता से समझ गए हैं कि,कॉपी पेस्ट जर्नलिज्म जिसे सम्मान से कॉपी कैट जर्नलिज्म लिखा गया है,उसकी व्यापकता क्या है ।एक अच्छी बात ये भी है कि,जिन्होंने ये अपने जिस भी माध्यम में परोसा,उनमें से किसी ने भी गलत सूचना/ब्रेकिंग पर कोई खेद व्यक्त नहीं किया। वैसे करना भी नहीं चाहिए। नीट मामले से लेकर कितने ही मामले होते हैं सरकार कभी खेद/माफी माँगती है क्या ? तो जब मालिक को यह संस्कार नहीं तो फिर नौकरों से यह लिहाज बरतने की उम्मीद क्यों की जाए।

इसे कहते हैं मौज लेना

सीएम हाउस में बैठक को लेकर शाम से रात तक जो भी गप्प,झूठ परोसा जाता रहा। इनसे इतर काँग्रेस की इस बैठक पर टिप्पणी है। कांग्रेस की ओर से सुशील भैया ने बयान जारी किया – ह्लजनता में सरकार और पार्टी से असंतोष है। पार्टी में सरकार से असंतोष है ।मंत्रियों में सीएम से असंतोष है। सीएम को मंत्रियों से असंतोष है ।पहले ये हुआ कि, मंत्रियों को हटाना है। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई तो सारे मंत्री सीएम हाउस पहुंच गए और वहां मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे थे ।ह्व

वो साध्वी सी नेत्री कौन हैं

रेत के खेल में सत्ता हमेशा शामिल रही है ।पहली प्रायोरटी ठेका मिलने में और ना मिले तो अवैध उत्खनन में, अब ऐसे में दो खेमें बन जाते हैं और मामला तलवार कट्टा तक पहुंच जाता है। उत्तर छत्तीसगढ़ के सोनहत में कुछ हुआ ऐसा ही है। अफवाहें इस मामले में एक साध्वी जैसे स्वभाव वाली राजनेता की ओर इशारा करती हैं। लेकिन भले लोगों(जिनमें सहाफी शामिल है) का यह मानना है कि सरल ह्रदय,षड़यंत्रों से कोई रिश्ता नहीं रखने वाली, जिनके भाव और प्रभाव देख गंगा मईया भी हाथ जोड़ लें ऐसी साध्वी जैसी इस महिला नेत्री को लेकर यह कहना कि इनकी सीधी सरपरस्ती अवैध रेत का कारोबार करने वालों के साथ डंके के चोट पर थी और मरने वाले रेत के ठेकेदार से निजी खुन्नस भी। यह सारी बातें बिलकुल झूट्ठी हैं ।एकदम झूट्ठी। यह बात तो और फर्जी है कि, घटना के पहले, घटना के दौरान और घटना के बाद मोबाईल पर सीधे और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए क्षण क्षण की सूचना वे लेती रहीं। सब राजनीतिक दुश्मन हैं जो साध्वी जैसी इस बेचारी नेत्री को परेशान करने अफवाह उड़ा रहे हैं।

एज पर रुल

कोरिया जिले में पति ने पत्नी पर चरित्र शंका का आरोप लगा बेरहमी से पिटा। मुंडन करा दिया ।हद तो ये कि,फिर महिला पर बच्चे से पेशाब करा चेहरे पर कालिख पोत खुद पेशाब भी पिला दिया। पूरी करतूत का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया ।अब इस मामले में पुलिस की कार्यवाही पूरे जोर से हुई है। बताते हैं पहले तीन धाराएँ लगाई गई जो जमानती थी ।एक अखबार ने खबर ठोक दी तो गैर जमानती धारा भी लगाई गई ।अब ऐसा क्यों हुआ कि झकझोर देने वाले इस कांड में पहले हल्की धाराएँ लगीं तो इसका जवाब एक खाकी वाले साहब ने यह कहते हुए दिया कि ह्लएज पर रुल्सह्व ही तो करेंगे ।जो घटना हुई है उसमें प्रारंभिक तौर पर जो दिखा वो सेक्शन लगा ।फिर जांच में कुछ और दिखा तो वो धारा भी जुड़ गई ।अब चुंकि साहब हैं तो जो बोले हैं वह सही ही होगा। लेकिन क़ानून के जानकारों का क्या करिएगा, वो चार धाराएँ और गिना रहे हैं जो और बड़ी सजा वाली है। चलिए ठीक है। अब मानिए कि पुलिस कह देती कि कोई अपराध ही नहीं बनता तो क्या कर लेता कोई। अरे भई कम से एफआईआर तो हुई,भले जमानती धारा लगी पर लगी तो सही। फिर एक गैर जमानती भी लगा दिए ।अब पुलिस से यह अपेक्षा भी करेंगे कि,विवेचना सटीक हो गवाहों को सुरक्षित करते हुए बयान करा लिया जाए और सजा भी हो। तो ऐसा है कि, निरीह पुलिस से ये अपेक्षा बहुत ज्यादा है।

अपनों ने लूटा

बबलू भईया एकदम ओंकारा हैं। याने सबसे बड़े लड़ईय्या रे ऽऽ धम धम धड़ैया रेऽऽ। भईया का पॉलिटिक्स ही ऐसा है कि पंगा अगर दूसरे रास्ते जा रहा हो तो खुदे घुम कर सामने आ जाते हैं कि,तुम उधर किधर जा रहे हो। भईया के इस फि तरत का ही कमाल है कि,पूरा चुनाव बीजेपी ने ह्लअब तो यह स्पष्ट है बबलू भईया भ्रष्ट हैंह्व कहकर निकाल दिया। लेकिन ढाई बरस में बबलू भइया को सारे इंतजाम अली भी लग भिड़कर कुछ कर नहीं पाए ।ईडी ने उनके पुतरु को उठाया टाँगा, तो सबसे तेज गति से बबलू भईया पूतरु को बाहर ले आए। जलवा भईया का देखिए कि, पुतरु को मिली जमानत को खारिज करने ईडी सुप्रीम कोर्ट गई और जब सुनवाई का समय आया तो ईडी ने ही वक़्त माँग लिया। इस पर चीफ जस्टिस नाराज भी हुए और उनकी टिप्पणी खासी चर्चित रही। लेकिन एक मसले में भईया उलझ रहे हैं। वह हैं उनके खिलाफ उन्हीं के भतीजे द्वारा लगाई इलेक्शन पिटीशन।

बताते हैं मसले को सुलझाने की जो कोशिश हुई वह उलटी पड़ गई ।अब इस याचिका की नियमित सुनवाई होनी है। वैसे बबलू भईया क़ि स्मत के सांड हैं ।ढाई साल तक किसी तरह मामला खींच गया तो बल्ले बल्ले। लेकिन यह भी है कि दूसरी तरफ भतीजा है, जिनकी अपनी क्वालिटी है।

खास खबर

कवर्धा के मुख्य बाजार में कपड़ा दुकान में भीषण आग, तीन मंजिला प्रतिष्ठान खाक

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की आशंका, देर रात तक चलता रहा राहत कार्य

शहर के मुख्य बाजार में सोमवार रात एक कपड़ा दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते तीन मंजिला पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया।

सामान निकालने का नहीं मिला मौका – प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान के भीतर रखे सामान को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने तत्काल दुकान संचालक, पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा कपड़ा, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो चुका था।

बंद करने के बाद लगी आग : पीड़ित व्यापारी नदीम अंसारी ने बताया कि वह रात करीब साढ़े नौ बजे दुकान बंद कर घर लौटे थे। कुछ देर बाद लोगों ने फोन कर आग लगने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे तो देखा कि शटर के भीतर पूरा प्रतिष्ठान आग की चपेट में था। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

जांच में जुटी पुलिस : फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। घटना के बाद बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई और देर रात तक राहत एवं बचाव कार्य चलता रहा।

उप मुख्यमंत्री ने नालंदा परिसर, मल्टी-लेवल पार्किंग और एसटीपी निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने दुर्ग में निर्माणाधीन नालंदा परिसर, इंदिरा मार्केट के पास मल्टी-लेवल पार्किंग एवं उरला में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान विभागीय अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों से कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों को कार्यों में तेजी लाते हुए तीनों कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित और जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में देरी नहीं होना चाहिए। इनमें देरी से नागरिकों को सुविधाएं मिलने में देरी होती है। श्री साव के कार्यों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह, महापौर श्रीमती अलका बाघमार और नगर निगम के आयुक्त सुमीत अग्रवाल भी मौजूद थे।

गधहाभाटा अब कहलाएगा सोनपुर, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामवासियों को सौंपी राजपत्र की प्रति

स्थानीय जनभावनाओं और सांस्कृतिक पहचान को मिला सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-कबीरधाम

कबीरधाम जिले के ग्राम गधहाभाटा का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर सोनपुर कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने शनिवार को ग्राम सोनपुर पहुंचकर ग्रामवासियों को राजपत्र की प्रति सौंपते हुए बधाई दी। इस दौरान ग्राम विकास के लिए उप मुख्यमंत्री ने 7 लाख 50 हजार रुपए के कई विकास कार्यों की घोषणाएं भी कीं। उन्होंने सामुदायिक भवन मरम्मत के लिए 2.50 लाख रुपए, किचन निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपए, गौठान समतलीकरण के लिए 1 लाख रुपए तथा पचारी निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की घोषणा की।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ग्रामवासियों की लंबे समय से गांव का नाम बदलने की मांग थी। स्थानीय लोगों की भावना और मांग को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया। इसके बाद मंत्रिमंडल स्तर पर चर्चा हुई, राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और अंततः राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया। उन्होंने कहा कि अब यह नाम सरकारी अभिलेखों और वेब पोर्टल में स्थायी रूप से दर्ज रहेगा। साथ ही ग्रामवासियों से अपील की कि वे भी अपने व्यवहार और दैनिक उपयोग में नए नाम सोनपुर को अपनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसी नाम से गांव की पहचान कर सकें। अब नई पहचान के साथ सोनपुर आगे बढ़ेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के नाम केवल पहचान नहीं होते, बल्कि वे स्थानीय इतिहास, संस्कृति और जनभावनाओं से जुड़े होते हैं। सोनपुर नाम परिवर्तन ग्रामवासियों के आत्मसम्मान और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने वाला सकारात्मक कदम है। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में एक अन्य गांव चांडालपुर का नाम भी बदलकर चंदनपुर किया गया है तथा उसका प्रकाशन भी राजपत्र में किया जा चुका है। ग्राम वासियों ने भी उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा का ग्राम को नई पहचान दिलाने में पहल करने के लिए आभार व्यक्त किया।

इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास प्लस नवीन सर्वे की स्थायी सूची के लिए 24 जून को विशेष ग्राम सभा में ग्राम पंचायत स्तर पर वाचन किया जाएगा, ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके, इस अवसर पर उन्होंने सभी को ग्राम सभा में अवश्य जाने की अपील की। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य राम कुमार भट्ट, पिपरिया नगर पंचायत अध्यक्ष घुरवा राम साहू, पूर्व विधायक डॉ. सियाराम साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

हीरानार छात्रावास पहुंचे मंत्री केदार कश्यप, विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने विकासखंड गीदम स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास, हीरानार का दौरा कर विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और व्यक्तित्व विकास के महत्व पर प्रकाश डाला।

विद्यार्थियों से मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करना और बड़े लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। उन्होंने बच्चों से निरंतर सीखने, मेहनत करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

संवाद के दौरान मंत्री श्री कश्यप ने विद्यार्थियों से हल्बी और गोंडी भाषा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को अपनी मातृभाषा, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही सच्ची पहचान है।

वन मंत्री श्री कश्यप ने विद्यार्थियों से सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे तथा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी ली। उन्होंने योग के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन एकाग्र रहता है, जिससे पढ़ाई में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि अगली बार उनके आगमन पर विद्यार्थी गीत, भजन, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें।

देश में सबसे तेज भुगतान कर भोरमदेव शक्कर कारखाने ने रचा इतिहास

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

देश के सहकारी शक्कर उद्योग में छत्तीसगढ़ के कवर्धा (कबीरधाम) स्थित भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने ने एक नया कीतिर्मान स्थापित किया है। लगातार दूसरे वर्ष यह कारखाना पूरे देश में गन्ना किसानों को समर्थन मूल्य और अतिरिक्त रिकवरी राशि का शत-प्रतिशत भुगतान जून महीने में ही पूरा करने वाला पहला शक्कर कारखाना बन गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के अवसर पर आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में गन्ना किसानों के खातों में 29.83 करोड़ रुपए की अंतिम किस्त सीधे ट्रांसफर की गई। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किसानों को चेक भी वितरित किए।

गन्ना किसानों को भुगतान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह समयबद्ध भुगतान केवल एक वित्तीय लेन-देन नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास और सहकारी मॉडल की बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि भोरमदेव शक्कर कारखाना किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि किसानों का अपना कारखाना है। निजी व्यवस्था में लाभ सीमित लोगों तक पहुंचता है, जबकि सहकारिता का लाभांश सभी हितधारकों में समान रूप से वितरित होता है। यह मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी जरिया है।

भोरमदेव शक्कर कारखाना के चेयरमैन एवं कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में इस सत्र में रिकॉर्ड भुगतान सुनिश्चित किया गया है। भुगतान के मुख्य आंकड़े में किसानों के खातों में आज 6.91 करोड़ रुपए की शेष एफआरपी राशि और 22.92 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रिकवरी राशि सहित कुल 29.83 करोड़ रुपए एकमुश्त राशि किसानों के खातों में अंतरित किए गए। सत्र 2025-26 का कुल भुगतान इस चालू सत्र में कारखाने द्वारा अब तक कुल 107.10 करोड़ रुपए (84.18 करोड़ रुपए एफआरपी $ 22.92 करोड़ रुपए अतिरिक्त रिकवरी) का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

उप मुख्यमंत्री ने किसानों से उन्नत कृषि तकनीक अपनाने और गन्ने का रकबा बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 6 हजार से अधिक किसानों ने कारखाने से अनुबंध किया था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 10 हजार किसान करने का लक्ष्य है। साथ ही कारखाने में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ना क्रशिंग का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की मांग पर बोनस राशि बढ़ाने के संबंध में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष यह विषय रखा गया है और इस पर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।

भोरमदेव शक्कर कारखाना पूरे देश में सर्वाधिक शुगर रिकवरी देने वाले कारखानों में शुमार है। पिछले दो वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां में शुगर रिकवरी लगातार तीसरे वर्ष 12 प्रतिशत से अधिक (वर्तमान में 12.09:) की शानदार शुगर रिकवरी दर्ज की गई। किसानों के लिए बलराम सदन कृषक प्रतीक्षालय का निर्माण, मिट्टी परीक्षण सुविधा, प्रेसमड वितरण और रियायती दर पर शक्कर का वितरण किया जा रहा है। लगभग 2,000 एकड़ क्षेत्र में उन्नत गन्ना बीज और सीडलिंग की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। कारखाना परिसर में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना कैंटीन के माध्यम से श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जा रहा है।

इस गरिमामय कार्यक्रम में कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण के सदस्य भगत पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी सहित भारी संख्या में प्रगतिशील किसान और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

संपादकीय

खुद बड़े नहीं हैं तो दूसरों को छोटा करने का प्रयास करते हैं

राजनीति में आदमी अपने काम से बड़ा होता है, अपनी सोच से बड़ा होता है,अपने आचार-विचार से बड़ा होता है। उसे मिल रहे सम्मान से बड़ा माना जाता है। चुनाव में लगातार मिल रही जीत से बड़ा होता है, लोकप्रिय होने से बड़ा होता है, लोग भरोसा करते हैं इसलिए बड़ा होता है। पीएम मोदी पिछले 12 साल से अपने काम से बड़े माने जाते है, अपनी सोच से बड़े माने जाते हैं,अपने आचार-विचार से बड़े माने जाते हैं,देश व विदेशों मे मिल रहे सम्मान व सवोच्च सम्मान से बड़े माने जाते हैं,सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए बड़े माने जाते है,लोग भरोसा करते हैं इसलिए बड़े माने जाते हैं,चुनाव में जनता उनको जिताती है इसलिए बड़े माने जाते हैं। देश के कई नेता न नाम से बड़े माने जाते हैं न काम से बड़े माने जाते है, न आचार विचार से बड़े माने जाते है,न अपने व्यवहार से बड़े माने जाते हैं ।लोकप्रिय नहीं है इसलिए बड़े नहीं माने जाते है, चुनाव नहीं जीतते है, इसलिए बड़े नेता नहीं माने जाते हैं। उनके छोटे होने में पीएम मोदी का कोई दोष नहीं है,लेकिन सब यही मानते हैं कि पीएम मोदी का कद हर तरह से हमसे बड़ा है,इसलिए हमें छोटा माना जाता है।

राहुल गांधी सहित ज्यादातर विपक्षी नेता अपना कद मोदी की तरह ऊंचा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, न उनका ऐसा कोई आचार-विचार और व्यवहार सामने आता है जिससे उनको मोदी के समान बड़ा नेता माना जाए तो उनकी मजबूरी है कि वह मोदी के राजनीतिक कद को छोटा करने का प्रयास करते हैं। खुद बहादुर नहीं हैं लेकिन पीएम मोदी की बहादुरी पर सवालिया निशान लगाएंगे, खुद निर्भीक नहीं है लेकिन पीएम मोदी की निर्भीकता का सवालिया निशान लगाएंगे। आपरेशन सिंदूर से और पाक के खिलाफ कई बार स्ट्राइक किए जाने से पीएम मोदी छबि बहादुर पीएम, घर मे घुसकर मारने वाले पीएम की बन गई है तो उनको विश्व के बड़े नेताओं,देशों के सामने खड़े कर छोटा साबित करने का प्रयास राहुल गांधी व कांग्रेस करते रहते हैं। वह पीएम मोदी को जितना छोड़ा बताने का प्रयास करते हैं, पीएम मोदी का कद देश के साथ ही विदेशों में और ऊंचा हो जाता है। विश्व के 33 देशों ने जिस नेता को अपना सवोच्च सम्मान दिया है, उसका सम्मान राहुल गांधी जैसे निरंतर चुनाव हारने वाले नेता के झूठे आरोपों से न तो पहले कम हुआ है और न आज कम हो सकता है।

देश के भीतर राज्यों के चुनाव होते हैं तो जनता उनको लगातार चुनाव में जिताकर उनके प्रति भरोसा जाहिर करती है तो राहुल गांधी अपनी पार्टी को न तो राज्यो में मजबूत कर पा रहे है और न ही चुनाव जिता पा रहे हैं तो वह हर चुनाव के बाद विपक्ष की नजर में और अपनी पार्टी के नेताओं की नजर में चुनाव हारे हुए नेता बने रहते हैं। हारे हुए नेता के तौर पर राहुल गांधी की छबि ऐसी बनी हुई है कि वह अकेले कांग्रेस को कई राज्यो मे जिता नहीं पाते हैं, वही गठबंधन वाले राज्यों में भी वह चुनाव जिताने में कोई सहयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनकी छबि चुनाव हारने व हरानेवाले नेता की बनी हुई है। इसलिए भी वह खीझ कर जब भी मौका मिलता है, पीएम मोदी को छोटा नेता, डरपोक नेता, सरेंडर करने वाला नेता, आदेश मानने वाला नेता बताने का प्रयास करते हैं। इससे राहुल गांधी की कद वास्तव में पीएम मोदी के बराबर तो होता नहीं लेकिन उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है कि पीएम मोदी से बेहतर नेता तो मैं हूं। रही सही कसर उनके आसपास के नेता अपनी चाटूकारिता से पूरी कर देते हैं, वह राजनीति की कड़वी सच्चाई से राहुल गांधी को अवगत कराने की हिम्मत नहीं कर पाते है ।वह दूसरे राहुल गांधी को देश का दूसरे नंबर का नेता बताकर उनके अहम को संतुष्ट करते रहते हैं। यह सच है कि राहुल गांधी पीएम मोदी के बाद देश के दूसरे नंबर के नेता हैं लेकिन यह भी सच है कि वह जब तक मोदी हैं वह दूसरे नंबर के ही नेता बने रहेंगे।

पीएम मोदी के पास पहले नंबर पर बने रहने की काबिलियत है और राहुल गांधी के बाद एक नंबर का नेता बनने की काबिलियत नहीं है इसलिए वह नंबर दो के नेता माने जाते हैं। वह सोचते हैं कि मैं ही तो नंबर दो हूं और मुझे ही एक दिन एक नंबर नेता बनना है,इसलिए वह सोचते हैं कि मैं पीएम मोदी का आलोचना करूंगा, झूठे आरोप लगाऊंगा तो लोग मुझे नंबर एक नेता एक दिन मान लेंगे। हाल ही ईरान-अमराकी युध्द के दौरान तीन भारतीय जहाजों पर हमला हुआ और तीन भारतीयों कि मौत हुए। भारत ने इसका हर स्तर पर विरोध किया। राहुल गांधी को मौका मिल गया और उन्होंने पीएम मोदी का कमजोर पीएम साबित करने के लिए कहा कि समझौतावादी पीएम अपने नागरिकों की सुरक्षा व सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता ।विदेशी ताकतें हमारे नागरिकों की हत्या करती है और हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह उनके आदेशों की पालन करती है। यह राहुल गांधी की पीएम मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने छोटा नेता बताने की कोशिश हैं ।हकीकत यह है कि भारत ने हर स्तर पर भारतीय जहाजों पर हमले का कड़ा विरोध किया, हकीकत यह है कि जब भी दुनियां में कही हजारों भारतीयों पर संकट आया है तो मोदी सरकार ने उनको बचाकर देश लाने में सफल रही है।

जी-7 देशों की बैठक के दौरान पीएम मोदी व ट्रंप की जब आमने सामने बात हुई तो पीएम मोदी ने तीन नाविकों ने हजारों भारतीयों की चिंता करते हुए कहा कि समुद्री व्यापार के क्षेत्र में दुनिया भर के अलग अलग समुद्रों में लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं ।मेरा मानना है कि उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ट्रंप से कहा कि पं.एशिया शांति समझौते में नाविकों की सुरक्षा को भी अहम स्थान दिया जाना चाहिए ।ट्रंप ने पीएम मोदी को आश्वस्त किया है कि नौपरिवहन जोखिम भरा काम है और नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। राहुल गांधी ट्रंप के सामने पीएम मोदी को छोटा बताने का मौका छोड़ते नहीं है और ट्रंप हैं कि कई मौकों पर पीएम मोदी को खुद से अच्छा बता चुके हैं, इस बार भी ट्रंप ने पीएम मोदी का तारीफ करते हुएकहा है कि पीएम मोदी शांत,संयमित व शानदार नेता हैं मैं ऐसा नही हूं. अब देश व दुनियां राहुल गांधी का बात पर कैसे यकीन कर सकती हैं कि पीएम मोदी ट्रंप से छोटे नेता हैं। उनका आदेश मानने वाले नेता हैं ।ट्रंप ने राहुल गांधी को फिर एक बार झूठा साबित कर दिया है।

विश्व वर्षावन दिवस : महत्व, उद्देश्य, थीम और संरक्षण के उपाय

सुनील कुमार महला

वर्षावनों के संरक्षण तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस (वर्ल्ड रेन फोरेस्ट डे) मनाया जाता है। वास्तव में, यह दिवस पृथ्वी के उन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को रेखांकित करता है, जो मानव जीवन, जैव-विविधता और जलवायु संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आज स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज लॉगिंग (पेड़ों की कटाई), अवैध खनन, अनियंत्रित विकास तथा कृषि विस्तार के कारण हर मिनट लगभग 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर वर्षावन नष्ट हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 50 वर्षों में अकेले अमेजन वर्षावन का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा समाप्त हो चुका है।

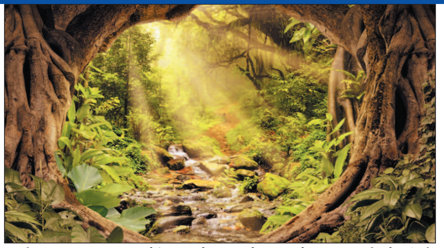

बहरहाल, यदि हम यहां पर इस दिवस के इतिहास की बात करें तो पाठकों को बताता चलूं कि विश्व वर्षावन दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 में गैर-लाभकारी संस्था रेनफोरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षावनों के संरक्षण के लिए विश्वभर के लोगों, संगठनों और सरकारों को एक साझा मंच पर लाना था। तब से यह दिवस विश्व के अनेक देशों में पर्यावरण संरक्षण अभियानों, वृक्षारोपण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मनाया जा रहा है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्षावन पृथ्वी के सबसे समृद्ध और जैव-विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र हैं। यद्यपि वे पृथ्वी की भूमि का अपेक्षाकृत छोटा भाग घेरते हैं, फिर भी इनमें विश्व की लगभग आधी से अधिक वनस्पति एवं जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा पृथ्वी के जल-चक्र और वर्षा प्रणाली को संतुलित बनाए रखते हैं। लाखों आदिवासी और स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका, संस्कृति और जीवन-निर्वाह के लिए वर्षावनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली 25 प्रतिशत से अधिक दवाओं के तत्व वर्षावनों के पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनमें अनेक कैंसर-रोधी औषधियाँ भी शामिल हैं।

इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को वर्षावनों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा उनके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। यह सरकारों, संस्थाओं और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने का संदेश देता है। पिछले वर्ष अर्थात 2025 में विश्व वर्षावन दिवस की थीम एमपावरिंग एक्शन (कार्रवाई को सशक्त बनाना) रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षावनों के संरक्षण हेतु जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने पर बल देना था। इस थीम के अंतर्गत स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने तथा उनके पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया था। वहीं वर्ष 2026 की थीम द फोरेस्ट विद इन यू (आपके भीतर का जंगल) है। यह थीम इस विचार को प्रस्तुत करती है कि वर्षावन भले ही भौगोलिक रूप से हमसे दूर हों, लेकिन हवा, पानी और जलवायु के माध्यम से वे हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा हैं। यह मनुष्य और प्रकृति के गहरे एवं आंतरिक संबंध को रेखांकित करती है।

वर्षावनों से जुड़े अनेक तथ्य अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण हैं। वर्षावन पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 3 प्रतिशत से भी कम हिस्से में फैले हैं, लेकिन वे विश्व की आधे से अधिक वनस्पति एवं जीव प्रजातियों का घर हैं। अमेजन जैसे विशाल वर्षावन हमारी सांसों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा स्वच्छ जल प्रणाली से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्हें अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के जलवायु संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज वर्षावनों के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियाँ हैं, जिनमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अवैध खनन, कृषि भूमि का विस्तार, अनियंत्रित औद्योगिक एवं शहरी विकास तथा जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। विशेष रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम ऑयल के बागानों के लिए बड़े पैमाने पर वर्षावनों की कटाई की जा रही है, जो वैश्विक चिंता का विषय है। इसी प्रकार मवेशी पालन और चरागाहों के विस्तार के लिए भी बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र नष्ट किया जा रहा है।

वर्षावनों के संरक्षण के लिए हमें जिम्मेदार उपभोग की आदत विकसित करनी होगी। कागज और लकड़ी के उत्पादों का सीमित एवं समझदारीपूर्ण उपयोग करना चाहिए तथा अनावश्यक खरीदारी से बचना चाहिए। पुनर्चक्रण (री-साइक्लिंग) को बढ़ावा देना आवश्यक है। कागज का दोनों तरफ उपयोग करना चाहिए, री-सायकल किए गए कागज और अन्य उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा जहाँ संभव हो डिजिटल विकल्प अपनाने चाहिए ।इसके साथ ही सतत (सस्टेनेबल) खरीदारी को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। सस्टेनेबल शॉपिंग का अर्थ है कि किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले यह विचार किया जाए कि वह कहाँ से आई है, उसका निर्माण कैसे हुआ है तथा उसके उपयोग के बाद पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें प्लास्टिक के बजाय कपड़े या जूट के थैले अपनाने चाहिए, ऑर्गेनिक तथा रीसायकल सामग्री से बने उत्पाद खरीदने चाहिए और स्थानीय तथा प्रमाणित उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए तो कम लेकिन टिकाऊ खरीदारी करनी चाहिए। पाम ऑयल से जुड़े उत्पादों के प्रति भी जागरूक रहना आवश्यक है। ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनमें पर्यावरण-अनुकूल और प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त पाम ऑयल का उपयोग किया गया हो। इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर मांस की खपत कम करने से चरागाहों के विस्तार की आवश्यकता घटेगी और वनों पर दबाव कम होगा। आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की परंपरागत समझ रखते हैं, इसलिए उनके अधिकारों और ज्ञान की रक्षा भी आवश्यक है। साथ ही ऐसी सरकारों और कंपनियों का समर्थन किया जाना चाहिए जो सख्त पर्यावरणीय कानूनों और शून्य-वनकटाई (जीरो-डीफोरेस्टेशन) नीतियों का पालन करती हैं।

अंत में यही कहूंगा कि वर्षावनों के संरक्षण के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, झूमिंग कृषि प्रणाली को हतोत्साहित करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना आवश्यक है। वन्यजीवों का संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विस्तार, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी आवश्यकता लोगों को वर्षावनों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में शिक्षित करने तथा व्यापक जन-जागरूकता फैलाने की है।

वास्तव में सच तो यह है कि वर्षावनों को बचाना किसी एक देश या सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण मानव समाज का सामूहिक और नैतिक दायित्व है। वर्षावन हमारे दैनिक जीवन, संस्कृति, स्वास्थ्य, जलवायु और भविष्य से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। वे हमें स्वच्छ वायु, संतुलित जलवायु, जैव-विविधता और जीवनदायी संसाधन प्रदान करते हैं। यदि हम आज इनके संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण, समृद्ध जैव-विविधता और सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकेंगे। इसलिए वर्षावनों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता ही नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की अनिवार्य शर्त भी है।

दल-बदल विरोधी कानून : स्थिरता की गारंटी या लोकतांत्रिक विवेक पर अंकुश?

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारतीय लोकतंत्र की सफलता का आधार केवल नियमित चुनाव नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही, राजनीतिक स्थिरता और जनादेश के प्रति निष्ठा भी है। संसद और विधानसभाएँ जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा इन संस्थाओं की स्थिरता लोकतांत्रिक शासन के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है। किंतु भारतीय राजनीति में लंबे समय तक दल-बदल की प्रवृत्ति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को गंभीर चुनौती दी। व्यक्तिगत लाभ, मंत्री पद, आर्थिक प्रलोभन अथवा राजनीतिक अवसरवाद के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि बार-बार अपनी निष्ठा बदलते रहे, जिससे सरकारें गिरती रहीं और जनादेश का अपमान होता रहा। इसी समस्या के समाधान के लिए 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित सदस्यों को राजनीतिक दलों के प्रति अनुशासित बनाए रखना तथा सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करना था।

हालाँकि समय के साथ यह कानून स्वयं बहस का विषय बन गया है। एक पक्ष इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार और अवसरवाद के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा कवच मानता है, जबकि दूसरा पक्ष तर्क देता है कि यह सांसदों और विधायकों की स्वतंत्र सोच तथा अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करता है। इस प्रकार दल-बदल विरोधी कानून भारतीय लोकतंत्र में स्थिरता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की जटिल बहस को जन्म देता है। दल-बदल की समस्या स्वतंत्रता के बाद के दशकों में तेजी से बढ़ी। 1967 के आम चुनावों के बाद अनेक राज्यों में विधायकों ने बड़े पैमाने पर दल बदले। उस समय आया राम, गया राम शब्दावली भारतीय राजनीति का प्रतीक बन गई। हरियाणा के विधायक गया लाल द्वारा एक ही दिन में कई बार दल बदलने की घटना ने इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया। इसके परिणामस्वरूप सरकारें अस्थिर हुईं, राजनीतिक नैतिकता कमजोर हुई और जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कम होने लगा। इसी पृष्ठभूमि में दल-बदल को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस हुई।

दसवीं अनुसूची के अनुसार यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। स्वतंत्र सदस्य किसी दल में शामिल नहीं हो सकता और मनोनीत सदस्य भी निर्धारित अवधि के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाता है। इस कानून के समर्थकों का तर्क है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे पहले, इसने सरकारों की स्थिरता को मजबूत किया है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि व्यक्तिगत लाभ के लिए बार-बार दल बदलते रहें, तो सरकारें निरंतर संकट में रहेंगी और प्रशासनिक निर्णय प्रभावित होंगे। दल-बदल विरोधी कानून ने इस प्रवृत्ति पर कुछ हद तक अंकुश लगाया है।

दूसरे, यह कानून राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करता है। अक्सर दल-बदल मंत्री पद, धन अथवा अन्य लाभों के लिए किया जाता है। ऐसे अवसरवादी व्यवहार से लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुँचती है। कानून का भय कम से कम खुले तौर पर होने वाले राजनीतिक सौदों को सीमित करता है। तीसरे, यह जनादेश की रक्षा करता है। मतदाता प्रायः किसी उम्मीदवार को उसके दल, विचारधारा और चुनावी घोषणापत्र के आधार पर चुनते हैं। यदि निर्वाचित सदस्य बाद में दल बदल लेता है, तो वह मतदाताओं के विश्वास को ठेस पहुँचाता है। इसलिए दल-बदल विरोधी कानून मतदाताओं की अपेक्षाओं की रक्षा का माध्यम माना जाता है।

चौथे, यह राजनीतिक दलों के भीतर अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि दल के सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकजुट रहें। यदि प्रत्येक सदस्य अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार मतदान करे, तो सरकार का संचालन कठिन हो सकता है। इन सकारात्मक पक्षों के बावजूद दल-बदल विरोधी कानून की आलोचना भी व्यापक रूप से होती रही है। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अंतरात्मा की स्वतंत्रता को सीमित करता है। संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सांसद और विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं, केवल राजनीतिक दलों के एजेंट नहीं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे किसी विधेयक या नीति पर अपने विवेक, अनुभव और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। किंतु व्हिप की बाध्यता के कारण उन्हें दल के निर्देशों का पालन करना पड़ता है, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो।

यह स्थिति लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करती है। संसद और विधानसभाओं का उद्देश्य केवल सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी देना नहीं, बल्कि गहन चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से बेहतर नीतियों का निर्माण करना है। जब सदस्य स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने से डरते हैं, तो बहस की गुणवत्ता प्रभावित होती है और विधायिका की भूमिका सीमित हो जाती है। कानून की दूसरी प्रमुख कमजोरी अध्यक्ष या सभापति की भूमिका से जुड़ी है। अयोग्यता संबंधी निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है, जो सामान्यतः किसी राजनीतिक दल से संबंधित होता है। कई मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि अध्यक्षों ने राजनीतिक हितों के अनुसार निर्णय लेने में देरी की या पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। इससे कानून की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

तीसरी आलोचना यह है कि कानून ने दल-बदल को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, बल्कि उसके स्वरूप को बदल दिया है। पहले व्यक्तिगत स्तर पर दल-बदल होता था, जबकि अब सामूहिक इस्तीफों और पुनर्निर्वाचन के माध्यम से सरकारें गिराई जाती हैं। हाल के वर्षों में कई राज्यों में विधायकों ने पहले इस्तीफा दिया और बाद में दूसरे दल में शामिल होकर पुनः चुनाव लड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि कानून की भावना को दरकिनार करने के नए तरीके खोज लिए गए हैं। चौथा, यह कानून राजनीतिक दलों के नेतृत्व को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है। दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जारी व्हिप का पालन करना सदस्यों के लिए अनिवार्य हो जाता है। इससे आंतरिक लोकतंत्र कमजोर पड़ता है और पार्टी के भीतर असहमति व्यक्त करने की गुंजाइश कम हो जाती है। परिणामस्वरूप निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं की बजाय पार्टी नेतृत्व की प्राथमिकताओं को अधिक महत्व देने लगते हैं।

इन आलोचनाओं को देखते हुए विभिन्न आयोगों और विशेषज्ञों ने सुधारों का सुझाव दिया है। विधि आयोग, राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग तथा कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि दल-बदल विरोधी कानून का दायरा सीमित किया जाए। उनका मानना है कि व्हिप केवल उन मामलों में लागू होना चाहिए जो सरकार के अस्तित्व से सीधे जुड़े हों, जैसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विनियोग विधेयक या अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय विषय। सामान्य विधायी मामलों में सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसी प्रकार अयोग्यता संबंधी निर्णय अध्यक्ष के बजाय किसी स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण अथवा निर्वाचन आयोग को सौंपने का सुझाव भी दिया गया है। इससे निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में निर्णय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त की है और समयबद्ध निपटान की आवश्यकता पर बल दिया है।

अन्य लोकतांत्रिक देशों का अनुभव भी इस बहस को रोचक बनाता है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे संसदीय लोकतंत्रों में दलगत अनुशासन तो है, किंतु भारत जैसी कठोर अयोग्यता व्यवस्था नहीं है। वहाँ सांसद कई बार पार्टी लाइन से अलग मतदान करते हैं, फिर भी उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। इससे संसदीय बहस अधिक स्वतंत्र और जीवंत बनी रहती है। दूसरी ओर भारत जैसी विविधतापूर्ण और गठबंधन-प्रधान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका अधिक रहती है, इसलिए यहाँ कुछ प्रकार के नियमन की आवश्यकता को भी नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि दल-बदल विरोधी कानून को पूरी तरह समाप्त करना व्यावहारिक समाधान नहीं होगा। भारत ने अतीत में अवसरवादी राजनीति और अस्थिर सरकारों के दुष्परिणाम देखे हैं। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि लोकतंत्र केवल स्थिरता का नाम नहीं है; यह विचारों की स्वतंत्रता, असहमति और विवेकपूर्ण निर्णय की संस्कृति पर भी आधारित है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि केवल पार्टी नेतृत्व के निर्देशों का पालन करने तक सीमित हो जाएँ, तो संसद और विधानसभाएँ लोकतांत्रिक विमर्श के मंच के बजाय औपचारिक संस्थाएँ बनकर रह जाएँगी।

इसलिए आवश्यकता संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की है। दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक भ्रष्टाचार और अवसरवाद को रोकना होना चाहिए, न कि वैचारिक बहस और लोकतांत्रिक असहमति को दबाना। व्हिप की अनिवार्यता को सीमित करना, निर्णय प्रक्रिया को स्वतंत्र बनाना, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना तथा जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को मजबूत करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। अंततः दल-बदल विरोधी कानून भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था है जिसने राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु इसके वतर्मान स्वरूप में कई लोकतांत्रिक चुनौतियाँ भी निहित हैं। लोकतंत्र की सफलता स्थिर सरकार और स्वतंत्र विचार, दोनों के संतुलन पर निर्भर करती है। इसलिए कानून में ऐसे सुधार आवश्यक हैं जो एक ओर जनादेश की रक्षा करें और दूसरी ओर निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने विवेक और जनता के हित में बोलने तथा निर्णय लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता भी प्रदान करें। यही संतुलन भारतीय संसदीय लोकतंत्र को अधिक परिपक्व, उत्तरदायी और सशक्त बना सकता है।

सत्ता पक्ष में जाने के बाद क्या बागी सांसदों को टिकट मिलेगा?

सौरभ वार्ष्णेय

भारतीय राजनीति में दल-बदल कोई नई घटना नहीं है। समय-समय पर विभिन्न दलों के नेता और सांसद राजनीतिक परिस्थितियों, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या वैचारिक मतभेदों के कारण अपने दल छोड़कर दूसरे दलों का दामन थामते रहे हैं। हाल के वर्षों में कई राज्यों में यह प्रवृत्ति और अधिक बढ़ी है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि सत्ता पक्ष में शामिल होने वाले बागी सांसदों को क्या अगले चुनाव में टिकट मिलेगा?

राजनीति में टिकट का निर्धारण केवल निष्ठा के आधार पर नहीं होता, बल्कि जीत की संभावना, जनाधार और पार्टी की रणनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्ता पक्ष आमतौर पर उन नेताओं को अपने साथ जोड़ना चाहता है जो चुनावी दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसलिए यदि कोई बागी सांसद अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार रखता है और उसके आने से पार्टी को राजनीतिक फायदा होता है, तो उसे टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

हालांकि यह भी सच है कि किसी दल में वर्षों से कार्य कर रहे पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए ऐसे फैसले असंतोष का कारण बन सकते हैं। जब बाहर से आए नेता को प्राथमिकता मिलती है, तो संगठन के भीतर नाराजगी बढ़ने का खतरा रहता है। कई बार यही नाराजगी चुनावी नुकसान का कारण भी बन जाती है। इसलिए राजनीतिक दलों को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है।

दूसरी ओर, बागी सांसदों के सामने भी चुनौती कम नहीं होती। दल बदलने के बाद उन्हें नए दल की विचारधारा, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी स्वीकायर्ता साबित करनी पड़ती है। केवल सत्ता पक्ष में शामिल हो जाना टिकट या राजनीतिक भविष्य की गारंटी नहीं है। यदि पार्टी नेतृत्व को लगता है कि संबंधित नेता चुनाव जिताने में सक्षम नहीं है, तो टिकट किसी अन्य उम्मीदवार को भी दिया जा सकता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल-बदल की बढ़ती घटनाएं राजनीतिक सिद्धांतों और जनादेश की भावना पर भी सवाल खड़े करती हैं। मतदाता किसी उम्मीदवार के साथ-साथ उसकी पार्टी और विचारधारा को भी ध्यान में रखकर मतदान करता है। ऐसे में बार-बार होने वाले राजनीतिक पलायन से जनता के बीच विश्वास का संकट पैदा होना स्वाभाविक है।

बागी सांसदों को टिकट मिलेगा या नहीं, इसका निर्णय राजनीतिक समीकरणों, जनाधार, संगठनात्मक संतुलन और चुनावी संभावनाओं पर निर्भर करेगा। लेकिन यह अपेक्षा अवश्य की जानी चाहिए कि राजनीति में अवसरवादिता के बजाय जनसेवा, सिद्धांत और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता मिले। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनावों से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की निष्ठा, सिद्धांतों तथा जनसेवा की भावना से तय होती है। दुर्भाग्यवश, हाल के वर्षों में दल-बदल, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और सत्ता प्राप्ति की राजनीति ने अवसरवादिता को बढ़ावा दिया है। इससे जनता के बीच राजनीति की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। राजनीति का मूल उद्देश्य समाज और राष्ट्र की सेवा है। जनता अपने प्रतिनिधियों को इस विश्वास के साथ चुनती है कि वे उनके हितों, समस्याओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन जब निर्वाचित प्रतिनिधि व्यक्तिगत लाभ, पद या सत्ता के लिए बार-बार राजनीतिक निष्ठा बदलते हैं, तो मतदाताओं का विश्वास कमजोर होता है। लोकतंत्र में यह स्थिति स्वस्थ नहीं मानी जा सकती।

सिद्धांत आधारित राजनीति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला होती है। विचारधारा, नीतियों और जनहित के मुद्दों पर आधारित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसके विपरीत अवसरवादिता राजनीतिक मूल्यों को कमजोर करती है और जनता में निराशा पैदा करती है। राजनीतिक दलों को भी ऐसे नेताओं को बढ़ावा देना चाहिए जो संगठन और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हों।

आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति में नैतिकता, पारदशिर्ता और जवाबदेही को सवोच्च प्राथमिकता दी जाए। जनप्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि उनकी पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति है, न कि व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के प्रति। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनसेवा को राजनीति का केंद्र बनाया जाएगा। राजनीति में अवसरवादिता के बजाय जनसेवा, सिद्धांत और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देना समय की मांग है। यही लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने और जनता के विश्वास को मजबूत करने का सबसे प्रभावी मार्ग है।

पान ठेले का ताला तोड़कर चोरी, 24 घंटे में नेवई पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

53 हजार की नकदी और सामान बरामद, नाबालिग साथी भी पकड़ा गया

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नेवई पुलिस ने पान ठेले का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से नकदी और सिगरेट-गुटखा समेत करीब 53,000 रुपये की चोरी गई संपत्ति बरामद हुई है। वारदात में शामिल एक विधि विरुद्ध बालक को भी पकड़ा गया है।

सुबह टूटा मिला था ताला

प्रार्थी ने थाना नेवई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 जून की रात करीब 10:30 बजे वह पान ठेले में ताला लगाकर घर चला गया था। 21 जून की सुबह 7 बजे ठेले पर पहुंचने पर ताला टूटा मिला। गल्ले में रखी नकदी और दुकान में रखा सिगरेट, गुटखा, माचिस, कोल्ड्रिंक समेत अन्य सामान गायब था।

बेचते पकड़े गए चोर

रिपोर्ट पर थाना नेवई में अपराध क्रमांक 404/2026 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक और एक विधि विरुद्ध बालक मोटर सायकल से घूमकर सिगरेट, गुटखा और कोल्ड्रिंक बेच रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी कार्तिक नाग उर्फ करन, उम्र 21 वर्ष, निवासी रिसाली भाठा, मोहन किराना के पास, भिलाई ने नाबालिग साथी के साथ मिलकर चोरी करना कबूल किया।

53 हजार की संपत्ति जब्त

आरोपी के कब्जे से चोरी की गई नकदी, सिगरेट, गुटखा, माचिस और कोल्ड्रिंक सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। कुल जप्त संपत्ति की कीमत लगभग 53,000 रुपये है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपने प्रतिष्ठानों और व्यवसायिक परिसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय अपनाने की अपील की है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को देने को कहा गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार साहू, प्रधान आरक्षक महावीर, आरक्षक रवि बिसाई, विजय कुर्रे और आरक्षक प्यारेलाल की सराहनीय भूमिका रही।

पत्नी को बचाने के चक्कर में पति की भी गई जान

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कपड़े सुखाने के लिए लगाए गए लोहे के जीआई तार में अचानक करंट आ गया। इसकी चपेट में पहले पत्नी आ गई और उसे बचाने की कोशिश में पति भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रा की है। जानकारी के मुताबिक, सचिन चन्द्राकर अपनी पत्नी रजनी के साथ घर पर थे। रजनी घर के काम निपटाकर आंगन में लगे लोहे के जीआई तार में कपड़े सुखाने गई थी और तार पर कपड़े डालते ही वो करंट की चपेट में आ गई। पत्नी की चीख-पुकार सुनकर सचिन तुरंत आंगन की तरफ भागे और पत्नी को बचाने की कोशिश की। जैसे ही सचिन ने रजनी को पकड़ा, वे खुद भी हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए। करंट इतना जोरदार था कि दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही जमीन पर गिर पड़े।

खास खबर

"सरकार की लाचारी से मनगटा बना शराबखोरी और अय्याशी का अड्डा" : रूपेश दुबे

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

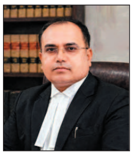

बिना डायवर्शन अवैध रिसॉर्ट जमींदोज करने की मांग, पूर्व सीएम के जिले में भी नहीं रुक रहा अनैतिक कारोबार

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने मनगटा क्षेत्र में बढ़ते अवैध कारोबार पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण मनगटा शराबखोरी, अय्याशी और देह व्यापार का केंद्र बिंदु बन गया है। प्रवक्ता दुबे ने कहा कि आए दिन मनगटा क्षेत्र में अवैध कारोबार के समाचार से पूरा क्षेत्र कलंकित हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और वतर्मान विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जिला होने के बावजूद ठोस कारर्वाई नहीं होने से अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई केवल दिखावे के लिए हो रही है, जिससे अनैतिक कार्यो में लिप्त कारोबारियों के सामने प्रशासन बौना साबित हो गया है।

"अवैध रिसॉर्ट जमींदोज करना ही उपाय" : रूपेश दुबे ने मांग की कि जिन रिसॉर्ट का डायवर्शन नहीं है, जहां अवैध निर्माण हुआ है, अनैतिक आपत्तिजनक सामग्री मिली है या शराबखोरी हो रही है, उन सभी को जमींदोज किया जाए। उन्होंने कहा कि अय्याशी और अघोषित देह व्यापार का केंद्र बनाकर सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ करने वाले रिसॉर्ट को ढहाना ही सीधा और सरल उपाय है।

"नोटिस की औपचारिकता से कुछ नहीं होगा" : दुबे ने बताया कि मनगटा में 150 से अधिक रिसॉर्ट हैं लेकिन मात्र 15 से 20 को नोटिस देकर जवाब लेने की औपचारिकता पूरी की जा रही है। इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्लाटिंग या कब्जे से ज्यादा खतरनाक ये अवैध व्यापारियों के रिसॉर्ट हैं क्योंकि इनके दुष्कृत्यों से क्षेत्र की संस्कृति और सभ्यता का क्षरण हो रहा है और अनैतिक वातावरण बन गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि क्षेत्र के बिना डायवर्शन वाले और अवैध रूप से निर्मित सभी रिसॉर्ट को जमींदोज किया जाए।

पौने दो साल से बनकर तैयार सार्वजनिक शौचालय का ताला आखिर कब खुलेगा?

दुर्ग। दुर्ग शहर के वार्ड नंबर 48 का उत्कल नगर शहर का एकमात्र ऐसा मोहल्ला है जहां के 70 प्रतिशत से ज्यादा घरों में निजी शौचालय नही हैं। ये झोपड़ी नुमा घर इतने छोटे हैं कि शौचालय बनाने की जगह ही नहीं है। वे वर्षो से सार्वजनिक शौचालय की बाट जोह रहे हैं। न्यू पुलिस लाईन के पास सार्वजनिक शौचालय बन भी गया है। थोड़ा सा ही काम बाकी है लेकिन निर्माण के बाद भी पिछले पौने दो साल से वहां ताला लटक रहा है। बचे हुए नाममात्र के काम को पूरा कर इस शौचालय का लोकार्पण करने में नगर निगम प्रशासन पता नहीं किस शुभ मुहूर्त की प्रतिक्षा कर रहा है? कांग्रेस के नगर निगम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अब्दुल गनी, देवकुमार जंघेल, लिखन साहू, वार्ड क्रमांक 48 पूर्व पार्षद महेश्वरी ठाकुर, पूर्व पार्षद अमृत लोढ़ा, संजय सिंह, भोला महोबिया, मनोज चंद्राकर, मनीष यादव, डॉ. छत्रसाल गायकवाड, राजकुमार वर्मा, युवराज ठाकुर, आदि ने उत्कल नगर के लोगों से चर्चा करने के बाद उक्त शौचालय का अवलोकन किया और निगम प्रशासन से मांग की है कि उसका जो पांच-सात प्रतिशत काम बचा है उसे तत्काल पूरा कराकर उसे प्रारंभ कराया जाए ताकि उत्कल नगर के बाशिंदों की विकट समस्या का समाधान हो सके, जो शौचालय के अभाव में कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर नित्यकर्म से निवृत्त होने जाते हैं। खासतौर पर महिलाओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले वे रेल पटरी के पास जाते थे लेकिन रेलवे प्रशासन ने सख्ती बरती और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर तक करा दी। ठगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण के बाद और ताल पुरी में फैंसिंग लगने के बाद अब उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। महिलाओं को तो अंधेरा होने की प्रतिक्षा करनी पड़ती है। उनकी इस समस्या का समाधान करने तात्कालीन पार्षद महेश्वरी ठाकुर के प्रयास से पहले बस्ती के पास ही सार्वजनिक शौचालय स्वीकृत हुआ लेकिन इसके लिए खोदे गए गड्ढे मे गिरकर एक बच्चे की मौत होने की दुखद घटना के बाद इसका विरोध होने से शौचालय निर्माण नहीं हो पाया। बाद में न्यू पुलिस लाइन के पास पुलिस कर्मियों के विरोध के बावजूद इसका निर्माण हुआ। थोड़ा सा ही काम बचा था और नगर निगम में सत्ता बदल गई। नतीजतन इसका काम रोककर वहां ताला जड़ दिया गया। इससे उत्कल नगर के लोग आज भी परेशानी उठा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व पाषर्दो ने नगर निगम प्रशासन से इसकी सुध लेकर इसे जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग की है।

खुर्सीपार में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का हुआ भंडाफोड़, तीन अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार

81 एटीएम, 62 पासबुक जब्त : गरीबों के नाम पर खुलवाते थे 'म्यूल अकाउंट',

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

दुर्ग पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन जुआ-सट्टा संचालित करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आईटीआई खेल मैदान खुर्सीपार के पास से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 13 मोबाइल, 11 सिम, लैपटॉप और हार्ड डिस्क समेत करीब 2.50 लाख की सामग्री जब्त की गई।

आईपीएल में रांची से चल रहा था नेटवर्क

21 जून को सहायक उप निरीक्षक तुलसी बिझेकर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आईटीआई खेल मैदान के पास बिजली पोल के नीचे तीन युवक लैपटॉप और मोबाइल से ऑनलाइन जुआ-सट्टा चला रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी 'अन्ना रेड्डी' ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन के जरिए सट्टा चला रहे थे। आईपीएल सीजन के दौरान गिरोह रांची, झारखंड से नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था।

गरीबों को लालच देकर खुलवाते थे खाते

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसों का प्रलोभन देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे। खाता खुलने के बाद पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल सिम अपने कब्जे में रख लेते थे। ऐसे खातों को 'म्यूल अकाउंट' कहा जाता है। इन खातों का उपयोग सट्टे से मिली रकम को ट्रांसफर करने, अवैध लेन-देन छिपाने और निकासी के लिए किया जाता था। पहचान छिपाने के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर, सिम और डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल होता था।

इन धाराओं में केस दर्ज

आरोपियों के खिलाफ थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 236/2026 धारा 318(2), 318(3), 318(4), 319 भारतीय न्याय संहिता और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 5, 6, 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बरामद डिजिटल उपकरणों और बैंक खातों का तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण जारी है।

गिरफ्तार आरोपी में अजय मिश्रा, 23 वर्ष, सेक्टर-01, एवेन्यू सी, भिलाई। दीपक कुमार, 32 वर्ष, ग्राम नगदोई, जिला नालंदा, बिहार। करण कुमार सिंह, 26 वर्ष, बालाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लेनोवो लैपटॉप 1, हार्ड डिस्क 1, मोबाइल 13, सिम 11, बैंक पासबुक 62, एटीएम कार्ड 81, चेकबुक 5। कुल कीमत करीब 2.50 लाख रुपए जब्त किया है।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल सिम या बैंकिंग दस्तावेज उपयोग के लिए न दें। ऐसे दस्तावेज साइबर अपराध, ऑनलाइन जुआ-सट्टा, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की सूचना निकटतम थाना या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।

कार्रवाई में थाना खुर्सीपार पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने अहम भूमिका निभाई। सउनि तुलसी बिझेकर, प्रधान आरक्षक बल्लूराम सपहा, पेट्रोलिंग स्टाफ और साइबर टीम ने सूचना संकलन, तकनीकी विश्लेषण और घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा।

कबीर जयंती : वार्ड 50 को मिली सामुदायिक भवन की सौगात, विधायक देवेंद्र यादव ने किया भूमिपूजन

बोले : संत कबीर की विचारधारा समाज को जोड़ने की प्रेरणा देती है

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

संत शिरोमणि कबीर दास जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर वार्ड क्रमांक 50, केनाल रोड स्थित कबीर वाटिका में कबीर जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को सामुदायिक भवन निर्माण की सौगात देते हुए भूमिपूजन किया।

जनभावनाओं पर तत्काल स्वीकृति

कार्यक्रम के दौरान साहू समाज एवं संत कबीर दास जी के अनुयायियों ने क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक भवन निर्माण की मांग रखी। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

समानता और भाईचारे का संदेश दिया कबीर ने

विधायक देवेंद्र यादव ने संत कबीर दास जी को नमन करते हुए कहा कि संत कबीर दास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और समाज को एकजुट रखने का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन बनने से क्षेत्र के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। यह भवन समाज की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा।

विकास कार्यो को प्राथमिकता

विधायक यादव ने कहा कि भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यो को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों की जरूरतों और मांगों के अनुरूप लगातार आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि प्रत्येक वार्ड में विकास का लाभ पहुंच सके। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजन, पदाधिकारी, संत कबीर दास जी के अनुयायी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

पुरानी भिलाई : साइबर ठगी के लिए खाता किराए पर देने वाला युवक गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

पैसों के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड साइबर ठगों को देने वाले आरोपी को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेनदेन के लिए किया गया था। म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग किए गए इस खाते में करीब 14,16,645 रुपये का संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिला है।

समन्वय पोर्टल से मिला इनपुट

भारत सरकार गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल और पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के आधार पर थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र में संचालित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खातों का परीक्षण किया गया। जांच में पता चला कि चिखली शाखा में संचालित एक खाते का उपयोग साइबर ठगी से संबंधित रकम के लेनदेन के लिए किया गया।

पैसे के लालच में दिया था खाता

विवेचना में सामने आया कि खाताधारक ने अपना बैंक खाता, पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड पैसों के लालच में अन्य व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया था। उक्त खाते को साइबर अपराध में म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया गया।

धारा 318 बीएनएस के तहत मामला दर्ज

प्रकरण में अपराध क्रमांक 258/2026 धारा 318(2), 318(3), 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी आकाश भट्ट, उम्र 22

वर्ष, निवासी अहिवारा, थाना नंदिनी, जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बैंक खाता संबंधी दस्तावेज, एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम कार्ड जब्त किए हैं।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग या सिम कार्ड उपयोग के लिए न दें। ऐसे कृत्य साइबर अपराध में संलिप्तता की श्रेणी में आते हैं और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। किसी भी साइबर ठगी की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या निकटतम पुलिस थाना में दें।

उतई पुलिस का नशे पर वार : अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उतई पुलिस ने अवैध शराब परिवहन और बिक्री करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग-अलग कार्रवाई में पुलिस ने 62 पौवा देसी शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की।

21 जून को थाना उतई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति बाइक क्रमांक उत्र 07 डअ 5938 से ग्राम पतोरा में अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर पुरेंद्र ठाकुर, 35 वर्ष, निवासी बोरहाडीह और शिवराम यादव, 50 वर्ष, निवासी चुनकट्टा को पकड़ा। तलाशी में प्लास्टिक बोरी से 32 पौवा देसी प्लेन शराब, 5.76 बल्क लीटर, कीमत करीब 3,200 रुपये बरामद हुई। दोनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 316/2026 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

दूसरी कार्रवाई मुक्तिधाम रोड, ग्राम पतोरा में हुई। यहां दिलेश कुमार पारधी, 24 वर्ष, निवासी गनियारी अवैध शराब बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। पुलिस ने रेड कर उसे पकड़ा। उसके कब्जे से 30 पौवा देसी मसाला शराब, 5.40 बल्क लीटर, कीमत करीब 3,000 रुपये जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 318/2026 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अधिक लाभ के लिए अवैध रूप से शराब का परिवहन और बिक्री कर रहे थे। कार्रवाई में थाना उतई के निरीक्षक अनिल कुमार पटेल, सउनि नरेंद्र सोनी, प्रधान आरक्षक मदनलाल साहू, आरक्षक महेश यादव, अविनेश प्रताप सिंह, ध्रुव नारायण चंद्राकर और दिलीप सिदार की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब, मादक पदार्थों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। नशे से जुड़े अपराधों में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

इंद्रजीत ने की जनकल्याण की मंगल कामना

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

'ए' मार्केट, सेक्टर-4, भिलाई स्थित श्री सर्वेश्वर धाम मंदिर के 12वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर आयोजित विशेष पूजा-अर्चना में सर्व कल्याण समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने शामिल होकर भगवान से देश, प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली तथा जनकल्याण की मंगलकामना की।

'मां इंटी बंगारम' का ओपनिंग डे कलेक्शन देखकर खुशी से झूमीं सामंथा

ओपनिंग डे पर सामंथा की फिल्म 'मां इंटी बंगारम' ने 5.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, वहीं दूसरे दिन इसने 2.54 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसका कुल कलेक्शन भी अब तक 7.89 करोड़ रुपये हो चुका है। फिल्म को देखने के लिए दर्शक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस बात की खुशी सामंथा को है। उन्होंने इस बात के लिए सोशल मीडिया के जरिए फैंस का आभार व्यक्त किया है।

महिला दर्शकों के योगदान का जिक्र सामंथा ने किया

एक्स (ट्वीटर) अकाउंट पर सामंथा लिखती हैं, 'पहले दिन किसी फिल्म की इतनी अच्छी ओपनिंग देखना बहुत ही खुशी का अनुभव है। यह बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यह देखकर बहुत खुशी होती है कि दर्शक फिल्म को अपना रहे हैं, चाहे वह मेल-लीड हो या फीमेल-लीड। यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि लोग पूरे दिल से फिल्म देखने आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ओपनिंग डे पर महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि थिएटर में ओपनिंग डे कलेक्शन पुरुष दर्शकों की वजह से होती है। सिनेमा के दर्शकों की संख्या का बढ़ना और बदलना बहुत अच्छी बात है। हमारे छोटे से प्रोडक्शन हाउस ने कमाल कर दिखाया।'

क्या है फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की कहानी?

'मां इंटी बंगारम' एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक पारंपरिक घर में नई बहू बनकर आती है। वह शांत, आज्ञाकारी और सबकी नजर में रहने वाली महिला है। लेकिन परिवार को यह नहीं पता कि वह क्या छिपा रही है। जब उसका दबा हुआ अतीत सामने आने लगता है, तो उसे उन्हीं लोगों की मदद करनी पड़ती है जो उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं। इस फिल्म को नंदिनी रेड्डी ने निर्देशित किया है।

फैमिली एक्शन-कॉमेडी ड्रामा है फिल्म

फिल्म का निर्देशन नंदिनी रेड्डी ने किया है। फिल्म 'मां इंटी बंगारम' एक फैमिली एक्शन-कॉमेडी ड्रामा है। इस फिल्म को सामंथा के पति और निर्देशक राज निदिमोरु ने बनाया है। इस फिल्म में दिगनाथ और गुलशन देवैया अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इनके अलावा फिल्म में श्री मुखी, गौतमी, आनंद और लक्ष्मी भी सपोर्टिंग रोल में दिखाई देंगे।

सामंथा ने किए हैं सारे एक्शन सीन्स

हाल ही में चेन्नई में हुए एक प्री-रिलीज इवेंट में समांथा ने फिल्म के एक्शन सीन को लेकर दिलचस्प बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में एक्शन बिल्कुल रियल है- ना कोई स्लो मोशन, ना ही उड़ने वाले शॉट्स और ना ही ज्यादा ड्रामा। समांथा ने कहा, 'फिल्म में जो भी फाइट सीन हैं, वो बिल्कुल असली लगेंगे। मुझे भी शूटिंग के दौरान कई बार चोट लगी, यहां तक कि खून भी बहा। लेकिन मैंने सारे एक्शन सीन खुद किए हैं, इसलिए ये इतने असली लगते हैं और लोगों को पसंद आते हैं।'

'वेलकम टू द जंगल' को लेकर क्यों घबराए हुए हैं सुनील शेट्टी

अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से पहले सुनील शेट्टी ने बताया कि बॉक्स ऑफिस को लेकर आज भी एक्साइटमेंट, टेंशन और घबराहट बनी रहती है।

बातचीत में सुनील शेट्टी ने कहा कि एक फिल्म की सफलता काफी हद तक उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, 'सब कुछ इससे जुड़ा होता है। एक शुक्रवार को आप टॉप पर हो सकते हैं और अगले शुक्रवार को नहीं भी हो सकते। इसलिए एक्साइटमेंट, टेंशन और घबराहट हमेशा रहती है।'

क्या है सेफ्टी नेट

इस पर सुनील ने कहा, 'इस फिल्म में बहुत शानदार स्टार कास्ट है- अक्षय, परेश जी, जॉनी भाई, अरशद, तुषार, श्रेयस, दलेर पाजी और कई दूसरे कलाकार। इतने टैलेंटेड लोगों के साथ काम करना एक तरह का सेफ्टी नेट देता है।'

मैं यह नहीं कह सकता कि यह अच्छी है या खराब

सुनील ने आगे कहा, 'फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह अच्छी है या खराब, क्योंकि हर किसी का नजरिया अलग होता है। जब हम फिल्म देखते हैं, तो हमें बहुत मजा आता है। लेकिन जब दर्शक शुक्रवार को इसे देखेंगे, तो उनका नजरिया बिल्कुल अलग हो सकता है।'

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय और सुनील शेट्टी के अलावा दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह भी हैं। इनके अलावा भी कई एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा हैं।

ग्राम चिकित्सालय- 2 में मेरा किरदार नई चुनौतियों का सामना करेगा

अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूर अपने वेब शो 'ग्राम चिकित्सालय' के दूसरे सीजन की रिलीज को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने शो के नए सीजन में अपने किरदार के सफर को लेकर खुलकर बात की। साथ ही बताया कि इस बार क्या खास है। अभिनेत्री ने बताया कि दूसरे सीजन में उनका किरदार गार्गी पहले से अधिक जिम्मेदारियों का सामना करता नजर आएगा। साथ ही, उसे कई कठिन और जटिल फैसले भी लेने पड़ेंगे, जो उसके किरदार के साथ कहानी को और भी दिलचस्प बनाएंगे। इस बारे में बात करते हुए आकांक्षा रंजन कपूर ने कहा, 'डॉ. गार्गी का किरदार निभाने का सबसे संतोषजनक पहलू यह रहा कि दर्शकों ने उससे गहरा जुड़ाव महसूस किया और भरपूर प्यार दिया। पहले सीजन में गार्गी को एक ईमानदार, सरल और जमीन से जुड़ी हुई महिला के रूप में दिखाया गया था और मुझे लगता है कि दर्शकों ने उसकी इसी सच्चाई से खुद को जोड़ा। यह देखकर खुशी होती है कि लोगों का यह प्यार और अपनापन दूसरे सीजन में उसके किरदार के और बड़े सफर का हिस्सा बना है।'

उन्होंने आगे कहा, 'दूसरे सीजन में गार्गी पहले से कहीं अधिक जिम्मेदारियों का सामना करती नजर आएगी। उसे कई जटिल फैसले लेने पड़ते हैं और ऐसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, जो उसके सिद्धांतों और विश्वासों की वास्तविक परीक्षा लेती हैं। एक कलाकार के तौर पर ऐसे शो का हिस्सा बनना बेहद संतोषजनक है, जो गहराई वाली कहानियां प्रस्तुत करता है और अपने किरदारों को विकसित होने का पूरा अवसर देता है।' 'ग्राम चिकित्सालय' के पहले सीजन को झारखंड के भाठकांडी गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के यथार्थवादी और संवेदनशील चित्रण के लिए काफी सराहना मिली थी। पहले सीजन में आकांक्षा रंजन कपूर ने स्थानीय डॉक्टर डॉ. गार्गी के किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया। शो की कहानी का बड़ा हिस्सा अब उनके किरदार के इर्द-गिर्द घूमता नजर आएगा, जिससे आकांक्षा रंजन कपूर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ग्राम चिकित्सालय का दूसरा सीजन 23 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा।

ऑस्कर विजेता कंपनी के साथ काम करेंगे ऋतिक रोशन

मशहूर हॉलीवुड प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कंपनी ने बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लिया है। यह कंपनी 'द रेवेनेंट' और 'स्पॉटलाइट' जैसी ऑस्कर जीतने वाली फिल्में बनाने के लिए जानी जाती है। ऋतिक ने 'एनोनिमस कंटेंट' कंपनी के साथ एक डील साइन कर ली है। इस डील के बाद से ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ऋतिक जल्द ही किसी बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं।

अभिनय, नृत्य और होस्टिंग में मुक्ति मोहन ने बनाई अलग पहचान

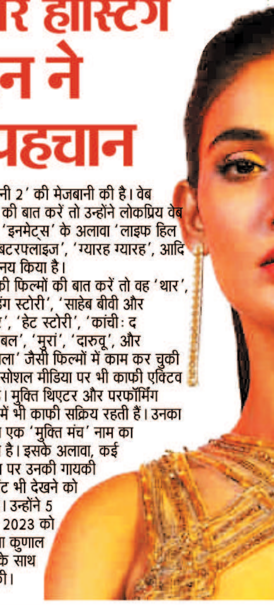

देश की जानी-मानी प्लेबैक सिंगर नीति मोहन और डांसर व कोरियोग्राफर शक्ति मोहन की बहन मुक्ति मोहन एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और डांसर हैं। मुक्ति मोहन ने कई फिल्मों, सीरियलों, वेब सीरीज और रियलिटी शो में अपनी एक्टिंग और हुनर का जादू बिखेरा है। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 2007 में विशाल भारद्वाज की शॉर्ट फिल्म 'ब्लड ब्रदर्स' से की। इसके बाद वह स्टार प्लस के एक डांस रियलिटी शो 'जरा नचके दिखा 2' में नजर आई, जहां उनकी टीम विजेता रही और इस उपलब्धि ने उन्हीं काफी प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस का जादू' और 'दिल है हिंदुस्तानी 2' जैसे टीवी शो में भी काम किया है। वह 'झलक दिखला जा' और 'नच बलिए 7' जैसे डांस रियलिटी शोज और 'फियर फैक्टर : खतरों के खिलाड़ी 7' में भी एक प्रतियोगी के तौर पर नजर आ चुकी हैं। मुक्ति ने डांसर, कोरियोग्राफर और टेलीविजन होस्ट राघव जुयाल के साथ सिंगिंग रियलिटी शो 'दिल है हिंदुस्तानी 2' की मेजबानी की है। वेब सीरीज की बात करें तो उन्होंने लोकप्रिय वेब सीरीज 'इनमेट्स' के अलावा 'लाइफ हिल गई', 'बटरफ्लाइज', 'ग्यारह ग्यारह', आदि में अभिनय किया है।

मुक्ति की फिल्मों की बात करें तो वह 'थार', 'अ वेडिंग स्टोरी', 'साहेब बीवी और गैंगस्टर', 'हेट स्टोरी', 'कांची : द अनब्रेकेबल', 'मुरां', 'दारुवू', और 'टॉपिवाला' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। मुक्ति थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी काफी सक्रिय रहती हैं। उनका खुद का एक 'मुक्ति मंच' नाम का स्टूडियो है। इसके अलावा, कई बार मंच पर उनकी गायकी का टैलेंट भी देखने को मिला है। उन्होंने 5 दिसंबर 2023 को अभिनेता कुणाल ठाकुर के साथ शादी की।

लोग कहते हैं कि ये कोई उम्र है क्या डांस करने की

हमारे समाज में औरतों के चरित्र को उसके कपड़ों की लंबाई से जज किया जाता है और सोसायटी की इसी सोच पर चोट करती है, माधुरी दीक्षित की नई फिल्म मां बहन। फिर में सोसायटी के तमाम नियमों को तोड़ने वाली रूल बेक्रर रेखा बनी माधुरी दीक्षित ने खुद भी लोगों के जजमेंट का सामना किया है, मगर वह उनकी परवाह न करके अपनी मर्जी के मुताबिक जीने में यकीन रखती हैं।

जो चीज खुशी दे, वो करना चाहिए

लोगों के जजमेंट को लेकर माधुरी कहती हैं, 'समाज में जजमेंट तो है ही। आप चाहे स्क्रीन पर हों या किसी भी प्रफेशन में, हमें जज किया ही जाता है, खासकर सिंगल औरतों को और भी ज्यादा। मतलब वे काम से लेट आईं तो लोग कॉमेंट करना शुरू कर देते हैं कि अरे, इतनी देर से आ रही है। ऐसे ही हमारे भी प्रफेशन में है कि अच्छा, अब तो मां बन चुकी है, अभी भी क्यों काम कर रही हैं या ये कोई उम्र है क्या डांस करने की? ऐसे कॉमेंट भी आते हैं, जिसका सामना करना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जजमेंट के बावजूद आपको वो करना चाहिए जो चीज आपको खुशी देती है। कॉमेंट्स करना उन्हें खुशी देता है लेकिन हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए।'

डांस से मुझे खुशी मिलती है

आज हम सोशल मीडिया के दौर में एज शेमिंग और वेट शेमिंग बहुत आम है। इस चलन पर माधुरी का कहना है, 'उम्र के साथ बदलाव आएगा ही। चेहरा बदलेगा, शरीर बदलेगा, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपकी जिंदगी में लोगों की सोच का इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए। आप वो करें जो आपको खुशी देता है। जैसे, मुझे डांस पसंद है तो मैं करूंगी क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है। आप लोगों के नजरिए से हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएं, लोग तो बोलते रहेंगे। हां, कभी-कभी बुरा बेशक लगता है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसे इतना सीरियसली न लें कि उससे आपकी जिंदगी प्रभावित होने लगे।' वहीं, 59 की उम्र में भी बेहद खूबसूरत और फिट माधुरी की फिटनेस का राज पूछने पर बताती हैं, 'इसके पीछे बहुत अनुशासन है। डायट का ख्याल रखना। एक्सरसाइज करना। मेरा डांस ही बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ सही समय पर सोना, कोई बुरी आदतें नहीं, वो सब मायने रखता है।'

मैन्युल पढ़कर नहीं बन सकते मां

फिल्म में दो जवान बेटियों की मां की भूमिका निभा रहीं माधुरी मांओं को एक ऊंचे मकाम पर खड़ा कर दिए जाने पर भी सवाल करती हैं। बकौल माधुरी, 'मां को हम एक ऐसे ऊंचे मकाम पर खड़ा कर देते हैं कि मां कुछ गलत नहीं कर सकती। उन्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उन्हें कुछ भी हो जाए, कितनी भी बीमार हो जाए, पर घर का ख्याल तो रखना ही चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो भी इंसान हैं और उन्हें भी उसी तरह से देखा जाना चाहिए। उनकी भी कभी तबीयत खराब होगी, वे भी आराम डिजर्व करती हैं।' वहीं, निजी जिंदगी में उनका अपने बेटों संग कैसा तालमेल रहता है? इस पर वह हंसकर कहती हैं, 'मां बनने का मतलब है केयास। उसके बाद उथल-पुथल ही रहता है जिंदगी में क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और आपको उन्हें समझना होता है। बच्चा किसी मैनुअल के हिसाब से तो पाला नहीं जा सकता।

बहुत तैयारी से आते हैं आज के ऐक्टर्स

माधुरी अपने दौर और आज नई पीढ़ी के कलाकारों, दोनों के साथ काम कर रही हैं। ऐसे में, इन दोनों पीढ़ियों के कलाकारों में वह क्या अंतर पाती हैं? यह पूछने पर वह बताती हैं, 'पहले के कलाकार जब इंडस्ट्री में आते थे तो दूर-दूर तक फिल्मों के बारे में कुछ पता नहीं होता था। हम बिल्कुल भी अनुभवी नहीं थे। हमें यह भी पता नहीं था कि सेट कैसे होते हैं। हमने काम करते-करते सब सीखा, लेकिन आज की पीढ़ी बहुत सारे ऐक्टिंग क्लासेस डांस क्लासेस करके आती है। उन्होंने ऐक्टिंग सीखी होती है। रील्स बनाए होते हैं। जैसे, मैं धारणा (इंफ्लूएंसर कोस्टार धारणा दुर्गा) को देखती हूं तो मुझे उन पर बहुत गर्व होता है क्योंकि वह खुद अपना कॉन्टेंट लिखती हैं। उनका आब्जर्वेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर उसे कॉमिडी में ढालती हैं और लोगों को हंसाती हैं, वह कमाल की चीज है। हमारे यहां वुमन कमीडियंस बहुत कम रही हैं। ऐसे में आज जब मैं देखती हूं कि लड़कियां स्टैंड अप कॉमिडी कर रही हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह तृप्ति ने बहुत कमाल की फिल्में की हैं, जिसके बाद उन्हें पहचान मिली है। इस फिल्म में भी उनका अभिनय लाजवाब है तो मुझे इन पर बहुत गर्व होता है कि इन्होंने बहुत कम समय में इतना कुछ हासिल किया है।'

दुर्ग की गौरव, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
मा. सरोज पाण्डेय जी को
जन्मदिन की
हार्दिक
शुभकामनाएं..
पुरुषोत्तम देवांगन
भाजपा जिला अध्यक्ष भिलाई
राजू खान
प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य
भाजपा अल्प जनसंख्यक मोर्चा (छ.ग.)

रेत खनन पर सख्ती : केंद्रीय उड़नदस्ते का रात में छापा, ड्रोन से नापी गई रेत

भंडारण में गड़बड़ी पर नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय खनि उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने 21 जून की रात एमसीबी जिले में औचक निरीक्षण किया।

ड्रोन सर्वे से पकड़ी गई गड़बड़ी

टीम ने तहसील केल्हारी के दंडाहस्वाही स्थित केवाई नदी, पसौरी, कुटरा और हसदेव नदी क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान स्वीकृत दो अस्थायी रेत भंडारण अनुज्ञप्ति स्थलों का विस्तृत परीक्षण किया गया। मौके पर उपलब्ध रेत की मात्रा का आकलन हाईटेक ड्रोन सर्वेक्षण से किया गया। निरीक्षण में भंडारण अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित रेत भंडारणकर्ताओं को कारण बताओ सूचना जारी की गई है। तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।

सीएम बोले : अवैध खनन के लिए कोई जगह नहीं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ खनिज संपदा का नियमानुसार दोहन सुनिश्चित किया जाए। अवैध खनन और भंडारण में संलिप्त पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी

खनिज सचिव पी. दयानंद ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के पहुंच-विहीन और संवेदनशील क्षेत्रों की सतत निगरानी की जाए। विभिन्न जिलों में अवैध रेत उत्खनन संभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर हाईटेक ड्रोन सर्वे के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इससे अवैध रेत खनन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

कार्रवाई में केंद्रीय उड़नदस्ता की संयुक्त जांच टीम और जिला स्तरीय टीम के अधिकारी मौजूद रहे। खनिज विभाग का मैदानी अमला जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी कर रहा है।

सीएम साय के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस, दुर्गम इलाकों में ड्रोन से निगरानी

आधी रात युवक की पत्थर से हत्या, शव खून से लथपथ मिला

खमतराई थाना क्षेत्र की हफ्र कॉलोनी के खुले मैदान में आधी रात एक अज्ञात युवक की हत्या कर दी गई। शनिवार रात खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर पत्थर से वार कर हत्या की गई है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। उसके दाहिने हाथ पर 'RK सारथी' नाम का गुदना गुदा हुआ है। पुलिस इसी निशान के आधार पर शिनाख्त की कोशिश कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही खमतराई पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वायड और FSL की टीमें मौके पर पहुंचीं। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगाल रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। खमतराई थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

अंतर्राज्यीय चेन स्नेचिंग गिरोह का पर्दाफाश, ओडिशा के 5 समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर। पुलिस ने शहर में महिलाओं को निशाना बनाकर चेन स्नेचिंग और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। एसीसीयू और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कारर्वाई में ओडिशा से संचालित इस गिरोह के कुल छह सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पांच आरोपी ओडिशा के और एक स्थानीय सहयोगी बिलासपुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार 15 जून को तोरवा क्षेत्र की शिवधाम कॉलोनी में महिला संजू कुमारी के गले से सोने की चेन झपटने की घटना हुई थी। इसके अलावा सिरगिट्टी क्षेत्र में भी महिला के साथ मारपीट कर चेन लूटने की वारदात सामने आई थी। दोनों मामलों की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक ही गिरोह की संलिप्तता पाई गई। जांच में बिना नंबर की नीली स्कूटी का उपयोग सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने सिरगिट्टी के गणेश नगर में दबिश देकर स्थानीय आरोपी नवीन साहू को हिरासत में लिया।

वैशाली नगर : सूने मकान में चोरी, आरोपी गिरफ्तार

39,900 के गहने बरामद, लोहे के रॉड से तोड़ा था ताला, दूसरा आरोपी फरार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

वैशाली नगर पुलिस ने सूने मकान में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड और चोरी किए गए 39,900 रुपये के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

केम्प-01 स्टील नगर वार्ड क्रमांक 28 निवासी बी. धनराजू ने 11 जून को थाना वैशाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 9 जून सुबह 11 बजे से 10 जून सुबह 6 बजे के बीच अज्ञात आरोपी ने उनके सूने मकान के मुख्य दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में प्रवेश किया। आरोपी ने आलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए।

रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमांक 220/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि संदेही सन्नी यादव चोरी के आभूषण बेचने की फिराक में इंदिरा चौक के पास घूम रहा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर सन्नी यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली।

आरोपी सन्नी यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी अटल आवास, इंदिरा गांधी कॉलेज के पीछे, जवाहर नगर, थाना वैशाली नगर के कब्जे से एक लोहे का रॉड, एक जोड़ी सोने का टाप्स कीमत लगभग 24,600 रुपये और एक सोने की अंगूठी कीमत लगभग 15,300 रुपये बरामद की गई। कुल मशरूका 39,900 रुपये का है। आरोपी को 21 जून को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में दूसरे आरोपी की तलाश जारी है।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि घर को लंबे समय तक सूना छोड़ने की स्थिति में पड़ोसियों और स्थानीय पुलिस को सूचना दें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100